A Daily News Magazine

इंदौर

शुक्रवार, 3 जनवरी, 2025

सुबह सवेरे

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 10 अंक 95, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2 (डाक पंजीयन संख्याः MP/IDC/1529/2016-2018)

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

दिल्ली चुनाव : यूपी-बिहार के मतदाताओं का रुख क्या रहेगा ?

दिलनवाज़ पाशा

गा़ज़ियाबाद की सीमा से सटे दिल्ली के बाहरी इलाक़े में पुश्ता रोड के ऊपर दिल्ली-देहरादून हाईवे का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। यहीं, वज़ीराबाद रोड पर नए मेट्रो स्टेशन खजूरी ख़ास का काम तेज़ी से चल रहा है। पुश्ता रोड और कच्ची कॉलोनी के बीच एक नाला है, जिसके एक छोर से कई गलियां कच्ची खजूरी कॉलोनी में दाखिल होती हैं।

ये कॉलोनी पिछले एक दशक में एक बड़ी आबादी का रिहायशी इलाक़ा बन चुकी है। यहाँ कुछ औरतें नालियों के पानी को घर में जाने से रोकने के लिए मशक्क़त कर रही हैं। दिल्ली की इस बाहरी कॉलोनी में अधिकतर प्रवासी रहते हैं। एक दशक पहले तक यहां छोटे-छोटे घर और झुग्गियां थीं। अब ये कॉलोनी नाम की ही कच्ची है, यहां अधिकतर मकान पक्के और कई मंज़िला हैं। सड़के हैं, बिजली हैं और पानी है लेकिन गंदगी भी बेशुमार है। मोहम्मद ज़ाहिद का परिवार बिहार से यहाँ आकर बसा था लेकिन अब यह परिवार दिल्ली का वोटर है। ज़ाहिद कहते हैं, 'बिजली, पानी, साफ़-सफ़ाई अपनी जगह हैं लेकिन दिल्ली में दो ही सबसे बड़े मुद्दे हैं, एक बेरोज़गारी और दूसरा लोगों के बीच बढ़ रही नफ़रत। सरकार अगर रोज़गार की समस्या का समाधान कर दे तो बाक़ी सभी मसले अपने आप ही हल हो जाएंगे। लेकिन, सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा उठा रही है।'

कच्ची खजूरी में कई लोग बिजली और पानी की व्यवस्था पर संतोष ज़ाहिर करते हैं लेकिन अधिकतर यहां पसरी गंदगी की तरफ़ इशारा करते हैं। दिल्ली में 1797 कच्ची कॉलोनियां हैं, जिनमें से अधिकतर में दिल्ली से बाहर से आए प्रवासी रहते हैं। इनमें भी सबसे बड़ी तादाद बिहार और पूर्वी यूपी से आए लोगों की हैं। इन्हें पूर्वांचली कहा जाता है। हाल के दिनों में दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश के बाद अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान के लिए अभियान चलाया है। दिल्ली पुलिस के जवान झुग्गी-बस्तियों और कच्ची कॉलोनियों में अवैध रोहिंग्या या बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए दस्तावेज़ जांच रहे हैं। हालांकि लोग इस तरह के अभियान पर सवाल ज़रूर उठाते हैं।

दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और बीजेपी इसे लेकर आमने-सामने हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी रोहिंग्या और बांग्लादेश से आए लोगों की पहचान के बहाने पूर्वांचल से आए लोगों पर निशाना साध रही है। एक प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने कहा, 'यूपी-बिहार से आकर बसे लोग, जो 30-40 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली के निर्माण का काम कर रहे हैं, उन्हें रोहिंग्या या बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है। बीजेपी एक सोची-समझी साज़िश के तहत ऐसा कर रही है क्योंकि दिल्ली के पूर्वांचल समाज आम आदमी पार्टी का वोटर है।'

केजरीवाल के इन आरोपों को ख़ारिज करते हुए दिल्ली बीजेपी के नेता बिपिन बिहारी कहते हैं, 'आम आदमी पार्टी ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को दिल्ली में बसाकर एक वोट बैंक बनाया है लेकिन दिल्ली के एलजी ने इस पर जांच बैठा दी है।' दिल्ली में अवैध रोहिंग्या या बांग्लादेशी लोगों की संख्या कितनी है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने दिसंबर महीने में 175 से अधिक संदिग्धों की पहचान करने का दावा किया है, जबकि दस से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की है। वहीं, चुनाव आयोग ने, फ़र्ज़ी आधार कार्ड के आधार पर वोटर पहचान पत्र बनाने का आवेदन देने के लिए कई लोगों पर मुक़दमा भी दर्ज कराया है।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग की कार्रवाइयों के बीच इस विवाद ने दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों को राजनीति के केंद्र में ला दिया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को जवाब देने के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मैदान में उतार दिया। सम्राट चौधरी ने दिल्ली पहुंचकर सम्राट चौधरी ने कहा, 'दिल्ली के एक बड़े नेता पूर्वांचल के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।'

दिल्ली में पूर्वांचल से आए लोगों की तादाद बढ़ रही है और ये कई सीटों के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करते हैं। ख़ासकर बाहरी दिल्ली के बाहरी इलाक़ों में बड़ी तादाद में पूर्वांचली रहते हैं। लोकनीति के सह-निदेशक संजय कुमार कहते हैं, 'पूर्वांचली वोटरों में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, जो ग़रीब या निम्न आय वर्ग से आते हैं।' इनकी संख्या का सही आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि कभी इसकी गणना नहीं हुई है। लेकिन, अलग-अलग अनुमान हैं। 'मैं ये मानता हूं कि दिल्ली में कम से कम 30 प्रतिशत तो पूर्वांचली मतदाता हैं। मोटे तौर पर 70 में से 20-22 सीटें ऐसी हैं, जहाँ पूर्वांचल वोटर निर्णायक संख्या में हैं।'

संजय कुमार कहते हैं, 'पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, बाहरी दिल्ली या यूं कहें कि केंद्रीय दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के महंगे इलाक़ों को छोड़कर जो इलाक़े हैं, वहां लगभग हर जगह पूर्वांचल से आए लोगों की बड़ी तादाद है। अधिकतर प्रवासी बाहर से आकर बसे और उन्होंने उन्हीं बाहरी इलाक़ों में पिछले 10 साल में पूर्वांचल के लोगों की राजनीतिक ताक़त भी बढ़ी है और राजनीति में उनकी संख्या भी बढ़ी है।'

हालांकि, पूर्वांचल के लोगों का मानना है कि उन्हें आबादी के हिसाब से राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। पूर्वांचल जन कल्याण समिति से जुड़े अधिवक्ता दया शंकर यादव कहते हैं, 'भले ही पूर्वांचल के लोगों की संख्या बढ़ी है, लेकिन राजनीति में उस हिसाब से भागीदारी नहीं है, किसी भी पार्टी में।' हालांकि राजनीतिक दल अब ये समझ रहे हैं कि दिल्ली में सत्ता तक पहुंचने के लिए पूर्वांचल के मतदाता अहम हैं और उन्हें नाराज़ नहीं किया जा सकता है।

विश्लेषक भी ये मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में पूर्वांचल के लोगों की राजनीतिक ताक़त बढ़ी है और पार्टियां उन्हें अपनी तरफ़ आकर्षित करने के प्रयास कर रही हैं। संजय कुमार कहते हैं, 'सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो संख्या के हिसाब से पूर्वांचल के लोगों का प्रतिनिधित्व नज़र नहीं आएगा। लेकिन, पिछले 10 सालों में दिल्ली की राजनीति में बदलाव आया है। अब राजनीतिक दल पूर्वांचल के मतदाताओं के महत्व को समझ रहे हैं और उन्हें अपनी तरफ़ आकर्षित करने के प्रयास कर रहे हैं। टिकट बँटवारे में भी इसका ध्यान रखा जा रहा है।'

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

अंतरिक्ष से अब सीधे की जा सकेगी मोबाइल कॉल

● ऐसा पहली बार, स्पेस एजेंसी इसरो की होगी अहम भूमिका ● अमेरिकी कंपनी का सैटेलाइट लांच करेगा भारत का इसरो ● आधे फुटबॉल मैदान के बराबर होगा एंटीना, तैयारी भी शुरू

नई दिल्ली (एजेंसी)। जल्द ही अंतरिक्ष से सीधे मोबाइल कॉल की जा सकेगी। इसमें भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की अहम भूमिका होगी। इसरो इस साल फरवरी-मार्च में एक अमेरिकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जिसकी मदद से किसी भी स्मार्टफोन के जरिए अंतरिक्ष से सीधे कॉल की जा सकेगी। यह पूरी तरह से कॉमर्शियल लॉन्चिंग है। इसे इसरो की कॉमर्शियल विंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंजाम देगी। अभी अंतरिक्ष से इंटरनेट और वॉयस कॉल के लिए स्पेशल हैंडसेट रखने या स्पेशल टर्मिनल रखने होते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टेक्सास की कंपनी स्पेसमोबाइल के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है। यह पहली बार है, जब कोई अमेरिकी कंपनी भारत से एक विशाल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करा रही है। भारत ने अब तक अमेरिकी कंपनियों के छोटे सैटेलाइट्स ही लॉन्च किए हैं। टीसी-3 से धरती की निचली कक्षा में स्थापित होगा ब्लूबर्ड स्पेसमोबाइल के टीसी एबेल एवेलन ने पिछले साल 'ब्लूबर्ड' के 'ब्लॉक 2 सैटेलाइट' को जियो-सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए लॉन्च करने की घोषणा की थी।

यूएस में ट्रक अटैक का आरोपी आईएसआई से प्रभावित

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स में 1 जनवरी की रात नए साल का जश्न मना रहे लोगों को एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने रौंद दिया। यह घटना रात के 3 बजकर 15 मिनट पर हुई। तब शहर की

सबसे व्यस्तम बॉर्बन स्ट्रीट पर हजारों लोग जश्न मना रहे थे। अचानक एक गाड़ी भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़ी। इसके बाद हमलावर पिकअप ट्रक से बाहर आया और लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई।

बिल्डर राजेश शर्मा की 250 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच

आयकर विभाग ने भोपाल-इंदौर के 56 ठिकानों पर मारे थे

भोपाल (नप्र)। भोपाल में आयकर विभाग ने त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक राजेश शर्मा की करीब 250 करोड़ की 24 प्रॉपर्टी अटैच कर ली है। विभाग ने आईजी पंजीयन और भोपाल के वरिष्ठ जिला पंजीयक को पत्र लिखकर कहा है कि राजेश शर्मा के स्वामित्व वाली किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं होने दी जाए। विभाग राजेश शर्मा के बयान लेने की तैयारी में भी है

बता दें कि प्रदेश में आयकर विभाग ने पिछले महीने त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ग्रुप, ईशान ग्रुप के संचालकों के 56 ठिकानों पर छापेमारी की थी। भोपाल के 53 और इंदौर के दो व ग्वालियर के एक ठिकाने पर की गई छापेमारी में आयकर विभाग को 10 करोड़ रुपए कैश और 25 से ज्यादा लॉकर की जानकारी मिली थी। एक हफ्ते तक चली छापेमारी की कार्रवाई में कई बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले थे। इसे आयकर टीम ने जब्त कर लिया था। इसके बाद दस्तावेजों की पड़ताल करने के बाद अब संबंधित लोगों को समन जारी किए जा रहे हैं। इनके बयान लेने की कार्रवाई शुरू हो गई है।

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर भी लगाई रोक-छापेमारी में यह खुलासा हुआ था कि ईशान ग्रुप, क्वालिटी ग्रुप और त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के कारोबार में राजेश शर्मा ही मास्टरमाइंड है। आयकर विभाग को आशंका है कि छापे की कार्रवाई के बाद शर्मा अपनी प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द कर सकता है और किसी को भी औने-पौने दाम पर बेच सकता है।इसके लिए भोपाल में रजिस्ट्री दफ्तर के सब रजिस्ट्रार तक यह निर्देश वरिष्ठ जिला पंजीयक के माध्यम से पहुंचाए गए हैं कि राजेश शर्मा के मालिकाना हक की किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन आयकर विभाग के संज्ञान में लाए बिना और अनुमति बिना नहीं किया जाएगा।

सुप्रभात

सब झूठा व्यवहार है दादा
कौन किसी का यार है दादा
छोड़ चुके हैं दुनिया वैसे
लेकिन कुछ दरकार है दादा
दो दिन का है खेल-तमाशा
दो दिन का संसार है दादा
बीच भँवर में डूब रहे हैं
अपनी नैया पार है दादा
चुप रहता है सब बातों पर
वो कैसा सरदार है दादा।

– डॉ.पूनम यादव

राजघाट के पास बन सकता है मनमोहन सिंह का स्मारक

केंद्र ने परिवार को जगह सुझाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने के लिए जमीन आवंटन का काम शुरू हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने स्मारक के लिए डॉ. सिंह के परिवार को कुछ जगहें सुझाई हैं। परिवार की तरफ से जगह का चुनाव हो जाने के बाद आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, गांधी-नेहरू परिवार की समाधियों के नजदीक ही डॉ. सिंह का स्मारक बनाए जाने की संभावना है। स्मारक के लिए एक-डेढ़ एकड़ जमीन दी जा सकती है।

सीएम यादव बोले-यूका के कचरे पर राजनीति न करें

भोपाल में लोग उसी के साथ रहते आए हैं, कचरा निपटान से नुकसान नहीं

भोपाल (नप्र)। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से पीथमपुर में निष्पादन के लिए कचरा ले जाने का विरोध तेज हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता इस कचरे को पीथमपुर में जलाने का विरोध कर रहे हैं। इस मामले पर हो रही राजनीति को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया।

● जनता की शंकाओं को दूर कर सावधानीपूर्वक किया जायेगा कचरे का विनिष्टीकरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सुझावों के आधार पर हमने भोपाल से यूनियन कार्बाइड का लगभग 358 टन कचरा, जिसमें 60 प्रतिशत से अधिक स्थानीय मिट्टी और 40 प्रतिशत केमिकल से जुड़े अपशिष्ट पदार्थ हैं, उसे पीथमपुर भेजा है। यह कचरा मुख्यतः कीटनाशक बनाने में उपयोग होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, इसका जहरीलापन 25 साल में लगभग खत्म हो जाता है।

घटना को 40 साल हुए, सभी आशंकाएं निराधार-डॉ. यादव ने कहा, इस घटना को 40 साल हो चुके हैं। इस दौरान कचरा भोपाल में ही रहा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कई

आशंकाएं निराधार हैं। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस कचरे के निपटान को लेकर गहन परीक्षण किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार की विभिन्न संस्थाओं जैसे नीरी (नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर), नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी और केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर किए गए अध्ययन और सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत किए गए सभी प्रतिवेदन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2013 में केरल के कोच्चि में 10 टन कचरे का ट्रायल रन किया गया था। इसके बाद, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 मेट्रिक टन कचरे पर ट्रायल की अनुमति दी, जिसे पीथमपुर में जलाया गया।

इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई और सभी रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गईं। अगस्त 2015 में यह ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रायोजित निपटान की सभी रिपोर्ट पुनः सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने प्रस्तुत की थीं।

रिपोर्ट्स से साबित, वातावरण को नुकसान नहीं-मुख्यमंत्री ने कहा, इन सारी रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि इस कचरे के निपटान से वातावरण में किसी प्रकार का नुकसान स्पष्ट नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिपोर्ट्स के गहन परीक्षण के बाद ही आगे बढ़ाने और इस कचरे को नष्ट करने के लिए निर्देशित किया।

इस मुद्दे का राजनीति न करें

पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी प्रकार का कष्ट न हो यह सब हमारे लिए विषय होता है। इसलिए हमने यहां के बाद दोपहर में उन सभी लोगों को विश्वास में लेकर चले और सारी जानकारी पारदर्शिता के साथ सामने रखें। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तत्कालिक राजनीति के बजाय हमें दीर्घकालिक समाधान पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने धार के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इस मामले पर जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने का निर्देश दिया है।

जनता के सरोकार प्राथमिकता में सबसे ऊपर है, कचरे के विनिष्टीकरण की कार्रवाई सतत् निगरानी में हो रही

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि यूनियन कार्बाइड के कचरे के विनिष्टीकरण के लिये सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। कचरे का निष्पादन जनता की शंकाओं को दूर कर सावधानीपूर्वक किया जायेगा।

विवेक शर्मा बने नए परिवहन आयुक्त

भोपाल । राज्य सरकार ने गुरुवार शाम मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त को बदल दिया है। अब 1998 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी विवेक शर्मा नये परिवहन आयुक्त होंगे । श्री शर्मा वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक योजना के पद पर पुलिस मुख्यालय में पदस्थ थे। मौजूद परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता की सेवाएं परिवहन विभाग से वापस लेते हुए उन्हें पुनः पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है। इसके अलावा 1996 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी योगेश चौधरी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रबंध को उनके कार्य के साथ आगामी आदेश तक योजना शाखा का भी अतिरिक्त प्रभार सोपा गया है । सूत्र बताते हैं कि परिवहन आयुक्त को हटाये जाने को हाल ही में परिवहन विभाग के एक पूर्व कर्मचारी के यहां पड़े छापे से जोड़ा जा रहा है।

मनु भाकर, गुकेश, हरमनप्रीत और प्रवीण को खेल रत्न

34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, 5 कोच को द्रोणाचार्य अवॉर्ड मिलेगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड 2024 का ऐलान गुरुवार को खेल मंत्रालय ने किया। ओलिंपिक में डबल मेडल जीतने वालीं शूटर मनु भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा 5 कोच को द्रोणाचार्य अवॉर्ड मिलेगा, इनमें 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हैं। 34 प्लेयर्स को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा, इनमें 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हैं।

17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में अवॉर्ड सेरेमनी होगी। मनु भाकर ने अगस्त-सितंबर में पेरिस ओलिंपिक गेम्स में डबल ओलिंपिक मेडल जीते थे। वे 10 मीटर एयर पिस्टल इंडीविजुअल और मिक्स्ड डबल्स में तीसरे स्थान पर रहीं। उनके दो मेडल के

दम पर भारत ने पेरिस ओलिंपिक में कुल 6 मेडल जीते थे। 18 साल के भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में 11 दिसंबर को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता था।

उन्होंने चीन के डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लिरेन को 7.5-6.5 से फाइनल में हराया। इतनी कम उम्र में खिताब जीतने वाले गुकेश दुनिया के पहले प्लेयर बने हैं। इससे पहले 1985 में रूस के गैरी कैस्परोव ने 22 साल की उम्र में यह खिताब जीता था। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलिंपिक 2024 में ब्रॉन्ज और एशियन गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं, हरमनप्रीत तीन बार के अवॉर्ड्स में प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीते हैं।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 18 °c न्यूनतम 13°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ शुक्रवार, 03 जनवरी 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

यूनियन कार्बाइड का 337-टन जहरीला कचरा 40 साल बाद हटा

भोपाल से 250 किमी दूर पीथमपुर ले गए ; कंटेनर निकालने आगे-पीछे 2-2 किमी ट्रैफिक रोका गया था

भोपाल (नप्र)। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा आखिरकार 40 साल बाद हट गया। भोपाल से बुधवार रात 9 बजे कचरे से भरे 12 कंटेनर हाई सिक्योरिटी के बीच पीथमपुर के लिए रवाना किए गए थे। कंटेनर आष्टा टोल पर पहुंचे तो 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया।

250 किमी का सफर करीब साढ़े 7 घंटे में तय कर गुरुवार सुबह 4.20 बजे सभी कंटेनर पीथमपुर के आशापुरा गांव स्थित रामकी एनवायरो फैक्ट्री पहुंचे। यहां इस कचरे को जलाया जाएगा। यहां भी रातभर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। इस बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। कंटेनर निकालने के लिए आगे-पीछे 2 किमी तक ट्रैफिक रोका गया।

कोहरे के कारण भी सफर थोड़ा मुश्किल रहा। कंटेनर्स के आगे पुलिस की 5 गाड़ियां थीं। 100 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। आष्टा के अलावा भी कुछ जगह जाम के हालात बने। 20 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भोपाल से ये जहरीला कचरा हटाया गया। इससे यूनियन कार्बाइड परिसर के 3 किलोमीटर दायरे की 42 बस्तियों का भूजल प्रदूषित हो चुका है।

कचरा पीथमपुर ले जाने की प्रोसेस 4 दिन चली- कचरे की शिफ्टिंग की प्रोसेस रविवार दोपहर से शुरू हुई थी। 4 दिन बैग्स में 337 मीट्रिक टन कचरा पैक किया गया। मंगलवार रात से इसे कंटेनर्स में लोड करना शुरू किया। बुधवार दोपहर तक प्रोसेस पूरी कर ली गई और रात में इसे पीथमपुर रवाना किया गया। दरअसल, हाईकोर्ट ने 6 जनवरी तक इस जहरीले कचरे को हटाने के निर्देश दिए थे। 3 जनवरी यानी शुक्रवार को सरकार को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करना है।

40-50 किमी/घंटे की स्पीड से चले कंटेनर

कचरा ले जाने वाले ये खास कंटेनर्स की स्पीड लगभग 40 से 50 किमी प्रति घंटा की स्पीड थी। रास्ते में कुछ देर के लिए रोका भी जा रहा था। कंटेनर्स के साथ पुलिस सुरक्षा बल, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और क्विक रिस्पॉन्स टीम मौजूद रही। हर कंटेनर में दो ड्राइवर थे।

हर घंटे जलाया गया था 90 किलो कचरा

पीथमपुर स्थित इंसीरेनेटर में 13 अगस्त 2015 को भी यूनियन कार्बाइड से 10 मीट्रिक टन जहरीला कचरा निष्पादन के लिए भेजा गया था। तब ट्रायल रन के तौर पर 3 दिन इसे जलाया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रायल रन के दौरान इंसीरेनेटर में हर घंटे 90 किलो कचरा जलाया गया था।

इसी ट्रायल रन रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार को यूनियन कार्बाइड कारखाने में रखे 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे का निपटान पीथमपुर में करने के निर्देश दिए हैं।

संक्षिप्त समाचार

लालू यादव के ऑफर को 'मुस्कुराकर' टाल गए नीतिश

सीएम ने खुजलाया गाल और प्रतिक्रिया देने से कर दिया इनकार

पटना (एजेंसी)। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से नये साल के मौके पर मुख्यमंत्री नीतिश कुमार को एक बार फिर से एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में आने

का न्योता मिला है। लालू प्रसाद यादव का ऑफर आने के बाद से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। गुरुवार को नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ उनके शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतिश कुमार से पत्रकारों ने लालू यादव के ऑफर पर उनसे सवाल पूछा तो वह इसपर जवाब देने से कतराते दिखे। नीतिश ने गाल खुजलाया, फिर मुस्कुराते हुए चले गए।

खालिस्तान समर्थक अमृतपाल बनाएगा नई पार्टी

14 जनवरी को माघी मेले में हो सकती है यह घोषणा

अमृतसर (एजेंसी)। असम की डिब्रूगढ़ जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत बंद खालिस्तान समर्थक और खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह 14 जनवरी को पंजाब की नई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे। श्री मुक्तसर साहिब में माघी पर्व के अवसर पर आयोजित माघी दा मेला के दौरान

इसकी घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर पंथ बचाओ, पंजाब बचाओ रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। रैली के दौरान अमृतपाल सिंह के पिता और उनके करीबी सहयोगी पार्टी की घोषणा करेंगे। वे सिख पंथ से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा में रहते हैं।

संभल में वक्फ प्रॉपर्टी की जांच कराएगा जिला प्रशासन

ओवैसी को दिया जवाब-नगर निगम के अंडर आती है पुलिस चौकी की जमीन

संभल (एजेंसी)। पिछले कुछ हफ्तों से संभल सुर्खियों में छाया हुआ है। इस बीच संभल जिला प्रशासन वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर सख्त हो गया है। संभल में मौजूद सभी वक्फ प्रॉपर्टी

की जिला प्रशासन जांच कराएगा। इसके लिए दो सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है। बता दें कि इससे पहले एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में बन रही पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी बताया था। ओवैसी ने कहा था कि संभल की जिस जमीन पर चौकी बन रही है, वह वक्फ की प्रॉपर्टी है।

हजारों फीट की ऊंचाई पर अब मस्त दौड़ेगा इंटरनेट

● एयर इंडिया ने शुरू की वाई-फाई सेवा, मुफ्त रहेगी सुविधा

नई दिल्ली (एजेंसी)। यात्रियों को यात्रा के दौरान इंटरनेट से जुड़े रहने का सपना अब हकीकत बन गया है। एयर इंडिया ने 1 जनवरी 2025 से अपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में वाई-फाई इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है। यह सुविधा एयरबस ए 350, बोइंग 787-9 और चुनिंदा एयरबस ए 321 विमान पर उपलब्ध होगी। इसके साथ ही, एयर इंडिया भारत की

पहली एयरलाइन बन गई है जिसने देश के भीतर उड़ानों में इन-फ्लाइट वाई-फाई की शुरुआत की है। खास बात यह है कि यह सेवा फिलहाल फ्री रहने वाली है। एयर इंडिया के मुख्य ग्राहक अनुभव अधिकारी राजेश डोगरा ने कहा, आज की यात्रा में कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। कुछ के लिए यह वास्तविक समय में साझा करने की सुविधा है, तो कुछ के लिए यह उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने का जरिया है। हमें विश्वास है कि हमारे यात्री इस नई सुविधा का स्वागत करेंगे और उड़ानों के दौरान कनेक्टिविटी का आनंद उठाएंगे। यह सेवा यात्रियों को वाई-फाई सक्षम उपकरणों जैसे लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन (एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम) के माध्यम से उपलब्ध होगी। 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर यात्री एक साथ कई डिवाइस कनेक्ट कर सकेंगे। यह सुविधा शुरुआत में मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि यात्री इसका अनुभव कर सकें।

सावरकर के नाम पर होगा दिल्ली का डीयू का कॉलेज

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एक कॉलेज का नाम स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के नाम पर रखने के फैसले ने कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी खींचतान को जन्म दे दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन जनवरी को वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज की

आधारशिला रख सकते हैं। डीयू की कार्यकारी परिषद द्वारा 2021 में अनुमोदित सावरकर कॉलेज नजफगढ़ में 140 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। अब इसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा, देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कई स्वतंत्रता सेनानी थे। अगर कॉलेज का नाम उनमें से किसी के नाम पर रखा जाता, तो यह उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती।

बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय प्रभु की जमानत याचिका खारिज

● चटगांव कोर्ट में आधे घंटे चली सुनवाई, अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय प्रभु दास की जमानत याचिका आज दूसरी बार खारिज हो गई। न्यूज एजेंसी डेली स्टार के मुताबिक चटगांव सेशन कोर्ट के जज सैफुल इस्लाम ने दोनों पक्षों की दलील पढ़ने के बाद ये फैसला दिया। इस मामले में करीब आधे घंटे तक सुनवाई चली। चिन्मय दास पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप है। इस मामले में राजद्रोह का केस दर्ज कर उन्हें 25 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। फैसले के बाद चिन्मय प्रभु के वकील अपूर्व भट्टाचार्य ने कहा कि वे जमानत

को लेकर हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह 10.15 बजे सुप्रीम कोर्ट के 11 वकीलों की टीम चटगांव कोर्ट पहुंची। इसके बाद करीब 11 बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान चिन्मय प्रभु को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। इससे पहले भी 3 दिसंबर 2024 को चिन्मय की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

18 राज्यों में भीषण कोहरे से हुई सुबह की शुरुआत

● लाहौल-स्पीति में पारा-16.7 डिग्री, जनवरी में सामान्य से ज्यादा तापमान रहेगा ● एमपी में 3 दिन कड़ाके की ठंड का अलर्ट, राजस्थान-यूपी में चल रही शीतलहर

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के 18 राज्यों में गुरुवार को कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक एमपी में अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी। बुधवार को लाहौल-स्पीति का ताबो गांव सबसे ठंडा रहा था, यहां तापमान -16.7 डिग्री रहा। कश्मीर घाटी में भी गुरुवार को बर्फबारी हुई। डोडा में वाटरफॉल जम गया। इस साल जनवरी में एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार और गुजरात के कुछ हिस्सों को छोड़कर बचे हुए क्षेत्र में मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा रहेगा। हालांकि उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर चलती रहेगी। उधर गुजरा हुआ साल 2024 सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग ने बताया कि 1901 के बाद 2024 देश में अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। साल के आखिरी तीन महीने (अक्टूबर-दिसंबर) में अब तक गर्मी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई

थी। अक्टूबर 2024 का महीना 123 साल में सबसे गर्म महीना था। 1901 से ही मौसम विभाग ने तापमान का रिकॉर्ड दर्ज करना शुरू किया था। 1991 से 2020 की अवधि के दौरान 2016 में औसत तापमान में 0.54 डिग्री सेल्सियस की वृद्ध दर्ज की गई थी।

2024 में इसमें 0.65 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। यानी 2016 और 2024 के तापमान में 0.11 डिग्री का अंतर दर्ज किया गया। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में ठंड बढ़ेगी, जनवरी में बारिश की भी संभावना महाकुंभ (13 जनवरी-26 फरवरी) के दौरान प्रयागराज में मौसम की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, महापात्र ने कहा कि हालांकि इस अवधि के दौरान रात में मिनिमम टेंपरेचर सामान्य से कम रहेगा। यानी ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख वाले उत्तर भारत में जनवरी में बारिश सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। 2.11 करोड़ पर्यटक 2024 में जम्मू-कश्मीर पहुंचे लद्दाख में 2023 में 5.25 लाख पर्यटक पहुंचे थे।

मोहन भागवत भगवान थोड़ी हैं, हमारा हर मंदिर खोजा जाए

● मुरादाबाद में यति नरसिंहानंद बोले-काबा खोदो वहां भी मंदिर मिलेगा

● कहा-हमें हर मंदिर वापस मिलना ही चाहिए, पुलिस ने बॉर्डर पर रोका

मुरादाबाद (एजेंसी)। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने गुरुवार को मुरादाबाद में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा- सऊदी अरब में जाकर काबा की खुदाई की जाए तो उसके नीचे भी मंदिर ही मिलेगा। मैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान से कतई सहमत नहीं हूं। मुरादाबाद आ रहे यति नरसिंहानंद को पुलिस ने जिले के बॉर्डर पर करीब एक बजे डिटेन किया था। नरसिंहानंद गिरी संभल हरिहर मंदिर समेत कुछ अन्य मुद्दों पर मुरादाबाद में प्रेस वार्ता करने वाले थे लेकिन, पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर ही रोक लिया। नरसिंहादनंद को पुलिस अपने साथ पाकबड़ा थाने ले गई है। यहां एसपी सिटी रण विजय सिंह ने यति नरसिंहानंद से कहा कि उन्होंने कार्यक्रम की पूर्व अनुमति जिला प्रशासन से नहीं ली है। इसलिए उन्हें मुरादाबाद में कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। यहां करीब डेढ़ घंटे तक पुलिस ने नरसिंहानंद को थाने में टीआई के कमरे में बैठाकर रखा। नरसिंहानंद ने कहा- मोहन भागवत क्या कहते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। भागवत भगवान नहीं हैं। सनातन धर्म के धर्मगुरु और हरे एक सनातनी यही चाहता है कि सनातन धर्म के जितने भी मंदिर हैं, वो आजाद कराए जाएं और उनका जीर्णोद्धार हो। दोपहर ढाई बजे यति नरसिंहानंद इस बात पर सहमत हो गए कि वो मुरादाबाद नहीं जाएंगे। इसके बाद उन्हें थाने से रिहा कर दिया गया। नरसिंहानंद को कार्यक्रम की परमिशन नहीं होने की वजह से रोका गया था।

ममता बनर्जी का दावा बीएसएफ करा रही बांग्लादेशियों की घुसपैठ

महिलाओं पर अत्याचार कर रहे, बंगाल में जानबूझकर अशांति फैलाई जा रही है

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को दावा किया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बांग्लादेशियों की घुसपैठ में मदद करती है, इसलिए बंगाल में अशांति फैल रही है। ये सब केंद्र सरकार का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि अगर बीएसएफ ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा

देना जारी रखती है, तो तृणमूल कांग्रेस उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। हमने कई बार केंद्र सरकार को इस बारे में बताया है। केंद्र जो भी फैसला लेगा हम उसे मानेंगे। हम केंद्र को एक विरोध पत्र भी भेजेंगे। बनर्जी ने कहा- बीएसएफ बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए तैनात है लेकिन वे इस्लामपुर, सीताई और चोपड़ा बॉर्डर से बांग्लादेशियों को भारत में एंट्री की परमीशन दे रही है। बीएसएफ महिलाओं के खिलाफ भी अत्याचार कर रही है। वे घुसपैठियों को बंगाल में आने देंगे और टीएमसी पर दोष मढ़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए नर्सरी बन गया है। बंगाल सरकार ने शुरू से ही बांग्लादेशियों के लिए लाल कालीन बिछा रही है।

भोपाल में यूनिफॉर्म-बुक खरीदने का दबाव डाला तो होगी एफआईआर

सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए आदेश जारी, 15 तक वेबसाइट पर देना होगी किताबों की जानकारी

भोपाल। नया शिक्षा सत्र शुरू होने के पहले भोपाल जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन, यूनिफॉर्म-बुक को लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक, किसी भी स्कूल या कॉलेज संचालक ने पेरेंट्स पर यूनिफॉर्म-बुक के लिए दबाव डाला तो एफआईआर दर्ज होगी। कलेक्टर ने स्कूल संचालकों की मनमानी पर धारा-144 के तहत पाबंदी लगाई है।

कलेक्टर सिंह ने प्राइवेट स्कूल-कॉलेज संचालकों, पुस्तक प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं का एकाधिकार खत्म करने के लिए आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत अब शहर के प्राइवेट स्कूल-कॉलेज के संचालक स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को निर्धारित दुकानों से ही यूनिफॉर्म, जूते, टाई, किताबें, कॉपियां खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। न ही किताबों के पूरे सेट खरीदने के लिए बाध्य किया जा सकेगा।

परीक्षा के बाद अप्रैल से खुलेंगे स्कूल-स्कूलों में फरवरी-मार्च में परीक्षाएं होंगी और अप्रैल में स्कूल फिर से खुलेंगे। इसी दौरान पेरेंट्स पर यूनिफॉर्म, बुक्स समेत अन्य शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है। पिछले साल भी कलेक्टर सिंह ने नए शिक्षा सत्र से पहले आदेश जारी किए थे।

कलेक्टर के आदेश में यह- कलेक्टर सिंह ने आदेश में कहा कि दवाब बनाए जाने से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स में नाराजगी होने के साथ तनाव की स्थिति भी बनती है। इसलिए यह आदेश जारी किया गया है। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए है। स्कूल संचालक आगामी शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पहले अनिवार्य रूप से लेखक एवं प्रकाशक के नाम, मूल्य के साथ कक्षा वार पुस्तकों की सूची स्कूल के सूचना पटल पर प्रदर्शित करें।

यूथ यूनियन के दो स्टूडेंट्स प्रदर्शन से पहले ही गिरफ्तार, भेजा जेल

डीडी पार्क में होने वाली थी मीटिंग; पुलिस बोली- बिना अनुमति करने वाले थे प्रदर्शन

इंदौर (नप्र)। एमपीपीएससी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करने वाले नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के दो सदस्यों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया था और गुरुवार को जेल भेज दिया। पुलिस ने दोनों पर धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा है। पुलिस का कहना है कि वे बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने की योजना बना रहे थे। इससे पहले भी एमपीपीएससी न्याय यात्रा के दौरान उन पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बुधवार को भंवरकुआं पुलिस ने नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के दो सदस्य राधे जाट और रंजीत को उनके घर से उठा लिया था।

वे दोपहर 12 बजे डीडी पार्क में एक मीटिंग करने वाले थे। बताया जा रहा है कि कम पदों पर भर्ती के विरोध में वे डीडी पार्क पर अभ्यर्थियों के साथ बैठक करने वाले थे। इसके लिए राधे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो स्टेटस डाला था, जिसमें उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से आने की अपील की थी। बुधवार सुबह,

जब अभ्यर्थी डीडी पार्क पर पहुंचने वाले थे, उससे पहले ही पुलिस ने राधे जाट और रंजीत किसानवंशी को उनके घर से उठा लिया। इसके बाद उनके साथियों ने नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस घटना की जानकारी दी। ट्वीट में उन्होंने सीएम डॉ. मोहन यादव, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, उमंग श्रृंगार सहित अन्य लोगों को टैग किया था।

रात तक परेशान होते रहे साथी- इधर, दोनों को पुलिस द्वारा उठाए जाने के बाद उनके साथी कई घंटों तक परेशान रहे। उन्होंने अलग-अलग थानों में जाकर उनकी जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चला। रात में साथियों ने एक वीडियो जारी कर कहा कि कई घंटों से पुलिस कोई जानकारी नहीं दे रही है। उन्होंने सभी छात्रों से अपील की कि सोशल मीडिया पर उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाएं। इसकी जानकारी भी उन्होंने ट्वीट के जरिए साझा की।

गुरुवार को भेज दिया जेल

गुरुवार को राधे जाट और रंजीत को जेल भेज दिया गया। उनके साथी हेमराज गुर्जर ने बताया कि गुरुवार को यह जानकारी मिली कि दोनों भंवरकुआं थाने में हैं। उन पर धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई थी। हम वकील लेकर भी गए, लेकिन कुछ नहीं हो सका। दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया गया और एसीपी के सामने पेश किया गया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। भंवरकुआं थाना प्रभारी राजकुमार यादव ने बताया कि राधे जाट और रंजीत पर धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है। बुधवार को वे बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने वाले थे, इसलिए कार्रवाई की गई। इसके पहले एमपीपीएससी न्याय यात्रा के दौरान उन पर धारा 188 के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।

इंदौर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

रेतीमंडी पर आईडीए के जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा; मौके पर भारी पुलिस बल तैनात

इंदौर (नप्र)। इंदौर में गुरुवार सुबह रेतीमंडी चौराहे के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। आईडीए की जमीन पर बने स्थायी और अस्थायी दुकानों, कुछ घरों और ढाबों को हटाया गया। इस कार्रवाई में 6 जेसीबी और 2 पोकलेन मशीनों के साथ नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची थी। जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई कोर्ट से आईडीए के पक्ष में फैसला आने के बाद की गई। 6 जेसीबी और 2 पोकलेन मशीन से की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई गई। आईडीए की स्कीम नंबर 97, पार्ट 4 में रेतीमंडी के पास यह कार्रवाई की गई। इस दौरान आईडीए द्वारा चिह्नित लगभग 40 स्थायी दुकानें, 15 अस्थायी दुकानें, 5 घर और 3 ढाबों को

हटाया गया।

आईडीए ने लिखा था लेटर

नगर निगम की डिप्टी कमिश्नर लता अग्रवाल ने बताया कि, गुरुवार को रेतीमंडी चौराहे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। आईडीए ने कमिश्नर को इस संबंध में पत्र भेजा था, जिसमें बताया गया था कि यह अतिक्रमण उनकी स्कीम क्षेत्र में है। कार्रवाई के दौरान कोई विवाद नहीं हुआ, क्योंकि आईडीए और नगर निगम ने लोगों को यहां से हटने के लिए पर्याप्त समय दिया था। इसी कारण अधिकांश दुकानें खाली मिलीं। कार्रवाई में नगर निगम का स्टाफ और पर्याप्त पुलिस बल शामिल थे।

बजरंगियों ने नाबालिगों को पुलिस को सौंपा

अश्लील हरकते करने का लगाया आरोप ; लव जिहाद के संदेह में कर दी पिटाई

इंदौर (नप्र)। इंदौर में लव जिहाद की शंका के चलते एक 17 साल के नाबालिग को पकड़कर चंदन नगर पुलिस के सुपुर्द किया गया है। बताया जाता है कि वह 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। पुलिस युवक को थाने ले गई। जहां बजरंगी भी कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचे हैं। बजरंग दल के पदाधिकारी तन्नु शर्मा को जानकारी मिली थी कि सिरपुर तालाब की पाल पर दिन में युवक एक युवती को लेकर बैठा है और अश्लील हरकत कर रहा है। सूचना के बाद तन्नु खुद अपने साथियों के साथ पहुंचे। जहां युवक की बजरंगियों ने पिटाई कर दी। युवक ने बताया कि वह सहयोग नगर में रहता है। वही मूल रूप से कन्नौद का रहने वाला है। लड़की से उसकी दोस्ती उसकी चचेरी बहन ने कराई थी। बजरंगियों के मुताबिक कार्रवाई के लिये लड़के को पुलिस के सुपुर्द किया गया है। साथ हीलड़की के परिवार से भी संपर्क किया गया है।

गुलाब की कलियां भेंट कर नशे से बचने की अपील

यातायात प्रबंधन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी चलाया अभियान

इंदौर (नप्र)। नए साल में शहर को नशा मुक्त बनाने एवं यातायात प्रबंधन व पर्यावरण के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रीगल तिराहे पर वाहन चालकों को गुलाब की कलियां एवं पर्चों का वितरण कर नशे से बचने की अपील की। नव वर्ष के आगमन पर यूनिवर्सल पीस एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी और सद्भावना प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा चौराहे पर शहर को नशा मुक्त बनाने के साथ ही यातायात व पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए वाहन चालकों को गुलाब की कलियां भेंट कर नए साल की शुभकामनाएं दीं। नशे के खिलाफ पर्चे वितरित किए। नशे खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का नेतृत्व डॉ. अनिल भंडारी, आलोक खरे एवं हाजी मुनीर खान ने करते हुए नागरिकों से अनुरोध किया कि शहर को नशा मुक्त, बेहतर यातायात प्रबंधन एवं पर्यावरण में भी नंबर वन लाना है, जो सभी नागरिकों के सहयोग से ही संभव है। इस आयोजन में फादर पायस, सैयद वाहिद अली, गुरमीत सिंह छाबड़ा, शफी शेख़, प्रणिता दीक्षित, शमसुद्दीन चिश्ती, राजीव परमार, प्राची परिहार आदि ने भी भाग लिया।

यूनियन कार्बाइड कचरे को लेकर इंदौर में

धार के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की बैठक; कहा- सीएम से मेरी बात हुई

इंदौर (नप्र)। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाकर नष्ट किया जाना है, जिसका पीथमपुर में कढ़ा विरोध किया जा रहा है। ऐसे में इस मुद्दे पर धार के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बैठक ले रहे हैं। बैठक इंदौर के एआईसीटीएसएल के सभागार में हो रही हैं। बैठक में विजयवर्गीय बोले कि सीएम से मेरी बात हुई है। सरकार जवाबदेही से काम कर रही है। आप चिंता मत करिए, मैं भी मालवा का बेटा हूं। उन्होंने बैठक में शामिल लोगों से कहा कि आप लोगों की संतुष्टि के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

आईएएस पोरवाल बोले– कार्बाइड के कचरे में 60 प्रतिशत मिट्टी

बैठक में शामिल आईएएस विवेक पोरवाल बोले अभी जो कचरा है उसमें 60 परसेंट सिर्फ मिट्टी है। कचरे के केमिकल कंपोजिशन में नेपथॉल-7 है। नेपथॉल-7 के बारे में वैज्ञानिक तर्क ये कहता है कि 25 साल में उसके सारे जहरीले प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाते हैं। भारत में इस कचरे को लेकर जितना अध्ययन हुआ है, उतना दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 12, केंद्र सरकार ने 13 कमिटियां कचरे के निपटान के लिए बनाई। आईआईटी जैसे कई संस्थानों ने कचरे पर रिसर्च

किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ट्रायल करने के लिए कहा। पीथमपुर में कोचिन की एक फैक्ट्री का सिंथेटिक कचरा लाकर जलाया गया। 59 पैरामीटर्स पर उसका अध्ययन किया गया। इसकी रिपोर्ट ठीक आने पर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड के कचरे पर ट्रायल करने को कहा। 2014 में दस टन कचरे पर ट्रायल हुआ। लंबे ट्रायल के बाद कचरा जलाने पर सहमति बनी है।

कचरा जलाने में लग सकते हैं 3 से 6 महीने

संचालक गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग के डायरेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मॉनिटरिंग में पूरी प्रोसेस चल रही है। करीब 337 टन कचरे को जलाने में करीब 3 से 6 महीने तक लग सकते हैं।

इंदौर बायपास होते हुए पीथमपुर पहुंचा कचरा

भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा 40 साल बाद इंदौर के पीथमपुर पहुंचना शुरू हो गया है। यह कचरा भोपाल से रवाना होकर लगभग 2:40 बजे पर इंदौर बायपास होते हुए पीथमपुर पहुंचा। 5,000 से ज्यादा मौतों का कारण बने इस जहरीले कचरे ने लगभग 8 घंटे में ढाई सौ किलोमीटर का सफर तय किया। कोहरे के कारण यात्रा और भी कठिन हो गई थी। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा पीथमपुर लाया गया है। इसके विरोध में पीथमपुर बचाओ समिति दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। इधर, पीथमपुर बस स्टैंड में चल रहा सर्वदलीय धरना खत्म हो गया है। अब स्थानीय नेता तीन जनवरी के बंद के समर्थन में घर-घर जाकर लोगों को इसमें शामिल करने के लिए प्रेरित करेंगे।

पीथमपुर की रामकी फैक्ट्री में ले जाया गया कचरा

337 मीट्रिक टन रासायनिक कचरे से भरे 12 कंटेनर बुधवार रात 9 बजे भोपाल से पीथमपुर के लिए रवाना किए गए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी कंटेनर सुबह 4:20 बजे पीथमपुर के आशापुरा स्थित रामकी फैक्ट्री पहुंचे। यहां कचरे का निष्पादन किया जाएगा। इसका विरोध तब से शुरू हो गया था, जब इसके निष्पादन का काम रामकी एनवायरो को सौंपा गया था।

सीएम बोले– इस पर राजनीति न करें

इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सारे सुझावों के बाद हमने भोपाल से यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर भिजवाया है। इस घटना को 40 साल हो चुके हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कई सारी आशंकाओं का अपने आप में उत्तर मिल जाता है। इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

दोस्त ने 5 साल तक लिवइन में रखा

शादी से इनकार किया, कहा- 'ऐसे ही रहो' ; युवती ने रेप का केस दर्ज कराया

इंदौर (नप्र)। इंदौर के भंवरकुआ इलाके में एक युवती ने अपने दोस्त के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया है। युवती का कहना है कि आरोपी, श्याम अहिरवार, ने उसे पांच साल तक लिवइन रिलेशनशिप में रखा, लेकिन अब शादी से इनकार कर रहा है। युवती का आरोप है कि श्याम ने शादी के कई वादे किए थे, लेकिन शादी को लेकर हमेशा टालमटोल करता रहा। पीड़िता ने बताया कि करीब छह साल पहले श्याम से उसकी मुलाकात हुई थी, और श्याम ने उसे लिवइन में रहने के लिए कहा, जिस पर वह राजी हो गई। दोनों ने एक फ्लैट किराए पर लिया और साथ रहने लगे। इस बीच, श्याम ने शादी के वादे किए और कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए, लेकिन शादी के लिए कभी गंभीर नहीं हुआ। नए साल की पार्टी के बाद, 1 जनवरी को जब युवती ने शादी की बात की, तो श्याम ने मना कर दिया और कहा कि वह शादी नहीं कर सकता, लेकिन अगर लिवइन में रह

सकती है तो ठीक है। इस पर युवती ने श्याम को धमकाने का आरोप भी लगाया और पुलिस थाने में जाकर उसके खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी श्याम को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

छात्रा के वीडियो एडिट कर भेजने वाले दो दोस्तों के खिलाफ केस

भंवरकुआ पुलिस ने 12वीं कक्षा की छात्रा के खिलाफ छेड़छाड़ और वीडियो एडिट कर उसकी सहेली को भेजने के मामले में दो दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज किया है। छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि रात के डेढ़ बजे उसकी सहेली ने कॉल कर बताया कि जगदीश शर्मा ने एक वीडियो भेजा है, जो अन टाइम व्यू था। वीडियो में फोटो को एडिट कर लड़की और लड़के को किस करते हुए दिखाया गया था। छात्रा ने मामले की जानकारी अपने भाई को दी और फिर जगदीश से कॉल पर पूछताछ की, तो उसने बताया कि यह फोटो पक्ष भंडारी ने भेजा था। छात्रा ने बताया कि वह दोनों लड़के कुछ दिन पहले एक पार्टी में मिले थे। पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है।

तेज सर्द हवाओं से इंदौर में कंपकंपी

तापमान में 3 डिग्री की गिरावट ; जनवरी के पहले हफ्ते में रहेगा सर्दी का असर

इंदौर (नप्र)। इंदौर में नए साल का पहला दिन और रात कंपकंपाने वाली रही। सर्द हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में 3 डिग्री की गिरावट आई। रात का तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुरुवार सुबह से हल्का कोहरा था। इसके साथ ही धूप निकलने के बाद तेज सर्द हवाओं के कारण कंपकंपी बनी हुई है। अभी जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में बर्फबारी जारी हो रही है। जिससे प्रदेश में सर्द हवाएं चल रही हैं। आने वाले दिनों में बर्फ पिघलने के साथ हवा की रफ्तार तेज होगी, जिससे ठंड का असर और बढ़ेगा। इसी कारण जनवरी में प्रदेश का मौसम ठंडा बना रहेगा।

इंदौर शहर-ग्रामीण अध्यक्ष का फैसला होल्ड होने की संभावना

ग्रामीण जिलाध्यक्ष कुर्सी की लड़ाई में शहर अध्यक्ष की कुर्सी पर भी फंसा पेंच

इंदौर (नप्र)। इंदौर बीजेपी और नगर अध्यक्ष की कुर्सी पर पेंच फंस गया है। जिससे दोनों ही अध्यक्षों की नियुक्ति होल्ड होने की संभावना है। दरअसल, ग्रामीण क्षेत्र की भाजपा में अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर घमासान है। वर्तमान अध्यक्ष चिंटू वर्मा को रोकने के लिए तीन विधायकों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। ऐसे में जिलाध्यक्ष की कुर्सी का फैसला अब दिल्ली से ही होना है और दिल्ली में भी विधायकों ने अपने-अपने स्तर पर उन्हें रोकने की तैयारी की है। सूत्रों के अनुसार चिंटू को रोकने के लिए अब दिल्ली में भी लाबिंग की जा रही है। ग्रामीण अध्यक्ष में पेंच फंसने से इंदौर शहर को लेकर भी घमासान शुरू हो गया है। मंत्री तुलसी सिलावट और उनकी विधानसभा के नेताओं ने तर दयाल का नाम बढ़ाया है।

आमने-सामने आ गए दो मंत्री

बीजेपी इंदौर ग्रामीण जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा को लेकर कहा जा रहा था कि उनके कार्यकाल को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है इसलिए उनको पार्टी रिपीट करेगी। लेकिन, रायशुमारी में सांवेर के विधायक और कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट के साथ ही पूरी विधानसभा के नेताओं ने वर्मा के नाम की जगह सिलावट के समर्थक अंतर दयाल का नाम देकर पेंच फंसा दिया। बताया जा रहा है कि यह पेंच फंसने के बाद देपालपुर विधायक मनोज पटेल और महू विधायक उषा ठाकुर ने भी वर्मा के खिलाफ नाम दे दिए हैं। पहले तो मंत्री सिलावट और सांवरे के नेता तय दिन पर रायशुमारी में शामिल नहीं हुए, उसके बाद रायशुमारी की तारीख बदली गई तो पूरी विधानसभा की तरफ से अंतर दयाल का नाम आगे बढ़ा दिया गया। राजनीतिक जानकारों की मानें इसे सीधे तौर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ देखा जा रहा है क्योंकि चिंटू वर्मा कैलाश विजयवर्गीय के खास समर्थक हैं। इंदौर का हर नेता यह जानता है कि चिंटू वर्मा का काम मंत्री विजयवर्गीय के बिना नहीं होता है। ऐसे में मंत्री सिलावट का रायशुमारी में शामिल नहीं होना और उसके बाद किसी अन्य नेता का नाम देना दोनों ही मंत्रियों आमने-सामने होने जैसा है। बता दें कि अंतर दयाल सिलावट के साथ सोनकच्छ के विधायक राजेश सोनकर के भी खास है।

दिल्ली तक हो रही ग्रामीण को लेकर लॉबिंग

ग्रामीण से वर्तमान में चिंटू वर्मा अध्यक्ष हैं और अभी उनका एक कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ है। राजेश सोनकर के सोनकच्छ विधायक बनने के बाद इस पद पर

कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में घनश्याम नारोलिया की नियुक्ति की गई थी, लेकिन उन्हें हटाकर स्थायी रूप से चिंटू वर्मा को अध्यक्ष बना दिया गया। देपालपुर विधानसभा सीट पर भी वे अपना दावा जता रहे हैं। इसी को लेकर उन्हें रोकने के लिए विधायक मनोज पटेल ने उषा ठाकुर और मंत्री तुलसी सिलावट से हाथ मिलाकर किसी दूसरे नाम की पैरवी की है। सूत्रों के अनुसार चिंटू को रोकने के लिए अब दिल्ली में भी लाबिंग की जा रही है।

ग्रामीण के कारण ऐसे अटका इंदौर शहर का नाम

दरअसल, इंदौर शहर का अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सांसद लालवानी और मंत्री विजयवर्गीय खेमे की पसंद का ही बनता है। मंत्री विजयवर्गीय के खेमे से चिंटू वर्मा का ग्रामीण अध्यक्ष दोबारा बनना तय माना जा रहा था जिसे देखते हुए विजयवर्गीय खेमे ने इंदौर शहर के लिए अपने किसी नाम पर ज्यादा जोर शुरुआत में नहीं दिया था। जिससे महाजन और लालवानी की पसंद का शहर अध्यक्ष बनना तय हो गया था। लेकिन ग्रामिण में पेंच फंसने की जानकारी मिलते ही विजयवर्गीय खेमे ने इंदौर से अपना नाम मजबूती से दे दिया। सूत्रों की मानें तो इंदौर 1, इंदौर 2 और इंदौर 3 से सुमित मिश्रा और दीपक टीनू जैन का नाम प्रमुखता से दिया गया। जिससे महाजन और सांसद की पसंद का अध्यक्ष बनना मुश्किल हो गया। वहीं राऊ विधायक मधु वर्मा और इंदौर 5 के विधायक महेंद्र हार्डिया ने फ्री फॉर ऑल कर दिया है। जबकि इंदौर 4 से मालिनी गौड़ खेमे से अप्रत्याशित रूप से गौरव रणदीवे का नाम आगे बढ़ा दिया गया। जिससे शहर और ग्रामीण में एक जैसे हाल हो गए।

इंदौर शहर अध्यक्ष के लिए इन नामों की है चर्चा

गौरव रणदीवे (42): वर्तमान शहर अध्यक्ष, विधानसभा लोकसभा चुनाव में सफलता मिली। बबलू शर्मा (46): वर्तमान एमआईसी सदस्य, वीडी शर्मा के करीबी तथा विधायकों का सपोर्ट। दीपक टीनू जैन (44): अभी प्रदेश सह मीडिया प्रभारी, पूर्व पार्षद, पूर्व महामंत्री युवा मोर्चा। समन्वय का नाम। इंदौर ग्रामीण अध्यक्ष के लिए इन नामों की है चर्चा चिंटू वर्मा (42): विधानसभा चुनाव के दौरान अध्यक्ष बने। दोबारा चुना जाना लगभग तय। घनश्याम नारोलिया (48): कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए।

संपादकीय

एक और कामयाबी की ओर कदम

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बीते साल के जाते-जाते एक दुर्लभ कामयाबी का एक और झंडा गाड़ दिया है। गत 30 दिसंबर को इसरो ने अपने नए मिशन 'स्पैडेक्स' को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। यह मिशन श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रात दस बजे लांच किया गया। स्पैडेक्स का अर्थ 'स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट' यानी अंतरिक्ष में यानों को 'डॉक' और 'अनडॉक' करना। अर्थात् अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यानों जो जोड़ने और अलग करने की तकनीक। इस मिशन का मकसद अंतरिक्ष यानों को 'डॉक' और 'अनडॉक' करने के लिए आवश्यक तकनीक का विकास करना और उसे दुनिया के सामने लाना है। इसे पीएसएलवी-सी60 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया किया गया। अगर यह मिशन पूरी तरह सफल रहा तो भारत स्पेस डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे हैं। इन देशों के बाद अब भारत ऐसा चौथा देश होगा, जिसके पास अपनी स्पेस डॉकिंग जटिल तकनीक है। गौरतलब है कि दो वर्षों तक चलने वाले इस मिशन के तहत पीएसएलवी-सी60 के जरिए दो छोटे अंतरिक्ष यान चेजर (एसडीएक्स01) और टारगेट (एसडीएक्स02) भेजे गए हैं। इनमें से प्रत्येक का वजन 220 किलोग्राम है। यह दोनों ही अंतरिक्ष यान, रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग होकर करीब 470 किलोमीटर की निचली कक्षा में स्थापित हो चुके हैं। आने वाले दिनों में इसरो के वैज्ञानिक दोनों यानों की बीच की दूरी कम कर उन्हें डॉक करने यानी जोड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें कि प्रक्षेपण के कुछ ही मिनटों बाद दोनों अंतरिक्षयान सफलतापूर्वक अलग हो गए। इसके बाद वैज्ञानिक स्पैडेक्स ए और स्पैडेक्स बी के बीच की दूरी को कम कर डॉकिंग और अनडॉकिंग की कोशिश करेंगे। इस दौरान यह 28 हजार 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चक्कर लगाएंगे। ये दोनों यान पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाएंगे। इनमें एक चेजर (एसडीएक्स01) और दूसरा टारगेट (एसडीएक्स02) नाम का उपग्रह है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ के अनुसार डॉकिंग की यह प्रक्रिया अगले एक सप्ताह में शुरू हो होगी। अब 7 जनवरी 2025 को इस मिशन में अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से दस गुना ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर रहे इन दो स्पेसक्राफ्ट्स को कनेक्ट किया जाएगा। मिशन के दौरान डॉक किए गए अंतरिक्ष यान के बीच पॉवर सप्लाई ट्रांसफर करने और अनडॉकिंग के बाद पेलोड संचालन करने का भी परीक्षण किया जाएगा, जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के दौरान मददगार साबित होगा। स्पैडेक्स मिशन की खासियत यह है कि यह एक किफायती तकनीक का प्रदर्शन करने वाला मिशन है। उल्लेखनीय है कि किसी भी अंतरिक्ष कार्यक्रम में 'इन-स्पेस डॉकिंग' तकनीक की जरूरत उस समय होती है, जब एक कॉमन मिशन को अंजाम देने के लिए कई रॉकेट लॉन्च करने की जरूरत पड़ती है।

इसरो के मुताबिक यह चंद्रयान-4 जैसे मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए भी अहम साबित होगा। साथ ही वहां से सैंपल लाने के साथ-साथ 2035 तक भारत के अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने जैसी योजनाओं के लिए बेहद अहम साबित होगा। भविष्य में स्पेस रोबोटिक्स जैसे प्रयोगों में भी यह अहम साबित हो सकता है। यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक एम शंकरन ने कहा कि अब तक इंडस्ट्री में कभी बड़े सैटेलाइट को अकेले नहीं बनाया गया था। यह पहली बार है कि दो सैटेलाइट इंटीग्रेट किया गया है। गगनयान मिशन के लिए भी ये टेक्नोलॉजी जरूरी है जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो ने इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी ले लिया है। क्योंकि कोई भी स्पेस एजेंसी इस बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बारीकियों को शेयर नहीं करती है। इस कामयाबी के लिए इसरो और उसके वैज्ञानिकों को बधाई।

2025 में भविष्य का नया रोडमैप जरूरी

नजरिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक भारत के राष्ट्रपति के ओएसडी रह चुके हैं। आप पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में चेयर प्रोफेसर हैं।

21वीं सदी के 25वें वर्ष का पड़ाव आ गया। जब 21वीं सदी में हम प्रवेश कर रहे थे तो हम पृथ्वी के लोग बहुत से ऐसे हिंसक चुनौतियों के दौर से गुजर रहे थे जिस पर हमारी आज की चिंताएं मामूली लगती हैं। असाध्य जैसा जो था, उसे कतिपय कारणों से हमने कम करने की कोशिश की लेकिन 2030 के सतत विकास का लक्ष्य भी कोई भी देश पूर्णतया नहीं हासिल कर सका, यह सचाई है। इस सदी के 25 वर्ष गुजरने जा रहे हैं। चुनौतियाँ बढ़ेंगी। घटने वाली नहीं हैं। हिंसा के रूप बदल सकते हैं लेकिन हिंसा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। लेकिन इसे नकारात्मक रूप से यदि हम अपने मन में बैठा लेंगे तो स्थितियां सामान्य भी नहीं होने वाली हैं बल्कि हमारे सामर्थ्य घटेंगे।

जैसा कि सम्पूर्ण विश्व आज आकलन कर रहा है कि हमारे पृथ्वी के खतरे बढ़े हैं। तापमान बढ़ा है। समुद्र खौल रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। यह प्रकृति का रूठना हमारे लिए भारी पड़ने वाला है। अब इसके कारणों में यदि जाकर विश्लेषण करें तो हमारे अपने क्रिया-कलाप ही इसके जिम्मेदार माने जाएंगे, कोई दूसरा इसके लिए दोषी नहीं कहा जाएगा। अपने सामर्थ्य से अधिक चुनौतियों का सामना करने की हम पृथ्वी के लोग हुंकार भरते रहते हैं, यह किसी समस्या का अंत करने वाला नहीं है। समस्या का अंत तो एक्शन से होने वाला है। एक्शन हमारे जीरो हैं। बातें बड़ी-बड़ी हैं।

किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए यह चिंता असहज कर सकती है। लेकिन असहज प्रकृति और पृथ्वी बनाने वाले शायद जब सोचना शुरू करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हमारी अधुनातन संस्कृति हमें भोग और विलासिता की दासी बना चुकी है। हमारी इच्छाओं ने हमें अपना दास बना दिया है। हमारे मूल्यों का पतन इस प्रकार हुआ है कि हमने सही दिशा में सोचना-समझना बंद कर दिया है। व्यक्ति-व्यक्ति से दूर हो चुका है। राष्ट्रों के बीच जो संधियाँ हैं वे केवल स्वार्थों में लिपटी हैं। वे सहयोग भाव से किसी राष्ट्र से नहीं जुड़े हैं। वे तो अपनी मार्किट एक्झिस्टेन्स के हिसाब से जुड़े हुए हैं। यह जो मार्केट है, यह हिंसा की जड़ है। द्वेष बढ़ाने का जरिया हैं, कोई माने या न माने। यह मार्केट पूरे पृथ्वी की सांस्कृतिक विरासत को चोट पहुंचाने जा रही है। इस सदी का देखते-देखते एक चौथाई वक्त बीत गया है।

मार्केट मोड भी अब बदल रहे हैं। छोटे-छोटे विज्ञापनों से आदिवासी लोगों की मनोभावनाओं पर वर्चस्व की राजनीति 2000 के बाद ज्यादा तेज हो गई थी भारत समेत दुनिया की उस आबादी तक जहाँ टेलीविजन अपना पांव पसार लिया था लेकिन यह तो छोटे व्यापार की कड़ी इससे तैयार हो रही थी। अब जब दुनिया में मार्केट मोड बड़े हथियारों को बेचने में लगे हैं। ग्रीन बेल्ट के ठेके हो रहे हैं और संसाधनों पर तेजी से कब्ज़ा करने की संस्कृति डिप्लोमेटिक तरीके से सेंध लगा रही है, तो सोचिये हिंसा का अनुपात किस प्रकार नए मोड में नया विस्तार पकड़ेगा? वर्चस्ववादी संस्कृति की हिंसा कुटिल भी होती है और जटिल भी होती है। वर्चस्ववादी संस्कृति का मनोविज्ञान बहुत ही क्रूर होता है। क्रूरता ही तो हिंसा है। इसमें फिर संदेह कहाँ रह जाता है कि हिंसा से मुक्त एक नया संसार भी इनसे बसेगा? मार्केट के माध्यम से हिंसा की यह खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। तीसरी दुनिया के लोग इससे सतर्क हो जाएँ। पुनरोद्धार के नाम पर, परिवर्तन के नाम पर, नई बीमारियों के आड़ में या फिर नए विमर्श के साथ वर्चस्व की राजनीति की जाती है। वर्चस्ववादी देशों के माध्यम से वर्चस्ववादी कॉर्पोरेट के लोग बहुत ही आहिस्ता से अपना कदम रखते हैं और अपने तरह के हिंसा का उत्खनन और उत्पादन करके अपनी लूट शुरू करते हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर एग्रीमेंट होते हैं। पर्यावरण के बचाव के लिए कॉर्पोरेट सहयोग की वकालत पिछले दिनों हुई थी। उसके सहारे कॉर्पोरेट के दूसरे एग्रीमेंट भी हुए हैं। वे अपने लिए विस्तार के माध्यम चुनते हैं और राज्यों के साथ जो समझौते करते हैं, उस समझौते के पीछे उनके हेतु जो जुड़े होते हैं, वे हानिकारक होते हैं। आमजन उसे बिलकुल नहीं समझता क्योंकि उसके लिए एग्रीमेंट कौन सा और कैसा हो रहा है, वह एक अबूझ पहेली होती है। संसाधनों का दोहन फिर शुरू हो जाता है। गरीबी और भुखमरी की ज्यादातर जटिल समस्याओं के पीछे ये कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं। हिंसा का मार्केट धीरे से अपना पांव जमाई। किसी को पता भी नहीं चला। यह होती है मंथर चाल से कब्जे की संस्कृति का चरित्र। इस प्रकार के बदलते हिंसा के स्वरूप जिस प्रकार से बढ़े हैं, बिलकुल चौंकाने वाले हैं। अफ्रीकी देशों में इसके असर बड़े पैमाने पर देखने को मिले हैं।

उदारवाद ने हिंसा को ज्यादा उगने, फलने-फूलने और विस्तारित होने दिया। 2025 इस सदी का निर्णायक वर्ष होना चाहिए जब उदारवाद को नए तरीके से परिभाषित किया जाए, नहीं तो हिंसा के व्याकरण आने वाले समय में समझने में आसानी नहीं होगी। अहिंसा की इच्छा फिर एक इच्छा रह जाएगी। 2025 इस सदी का वह समय है जब हम अपने वर्ष 2100 के समय की पीढ़ी के इतिहास, भूगोल, संस्कृति और उनके भाग्य के लिए अपना विजन प्लान तैयार करेंगे। इसे यूं ही निकलने देने से एक बड़ा नुकसान आने वाली पीढ़ी के लिए होने वाला है, जिसका शायद आज हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं।

पृथ्वी के लोगों के मन, मस्तिष्क, जीवन-आचरण की भौतिक व आध्यात्मिक शक्ति का निरूपण वर्ष है 2025। इस पड़ाव पर अपने हेतु यदि सही हुए तो एक बर्बर व जटिल समाज से निकलकर हम नए सहिष्णु व शांतिप्रिय समाज का निर्माण कर सकेंगे। शायद यही समाज हिंसक समाज के बरक्स अहिंसक समाज की परिभाषा बने। जल, जंगल, जलवायु, कृषि, विज्ञान, दर्शन, साहित्य और संस्कृति, अध्यात्म और अनेक विषद विषयों पर नई सोच के लिए एक नई उर्बर जमीन तैयार करना कोई आसान बात नहीं है। राज्यों का क्या है। सत्तासुख में सिमटी सरकारें अपने समय का सच्चा लाभ लेकर किनारे होने के लिए तैयार हैं। वे इन विषयों में आमूलचूल परिवर्तन के लिए कोई कदम उठाने के लिए तैयार बिलकुल नहीं हैं। राज्यों की विवशता कॉर्पोरेट घराने हैं जो विकास के नए पैमाने तय करके और चमकदार भविष्य के सपने दिखाकर अपना काम बना लेते हैं। आज वैश्विक स्तर पर समिट फॉर फ्युचर का आयोजन हुआ। उसमें जो चिंताएं व्यक्त की गयीं। उस पर गौर करें। एक वर्ष बाद भी कुछ सार्थक परिणाम देने वाले डाटा ये राज्य नहीं दे पाएंगे। यही इनका तो सामर्थ्य है, फिर ये नई उर्बर जमीन कैसे तैयार करेंगे? ये अपने आने वाले वर्ष 2100 के लिए कितना बेफिक्र हैं, बस इससे अंदाज़ा लगा लीजिए।

उलझे हुए संघर्ष, संगठित अपराध, शहरी और घरेलू हिंसा, हिंसक उग्रवाद, नई तकनीकें व एआई जनित हिंसा, परमाणु ख़तरे के मामले तेजी से हमारे लिए चुनौती बन रहे हैं। संघर्ष और हिंसा की प्रकृति में व्यापक बदलाव आया है। संघर्ष यदि कम घातक होते नज़र आ रहे हैं तो अक्सर राज्यों के बजाय घरेलू समूहों के बीच के संघर्ष हमारी नींद उड़ने वाले होते हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में हत्याएं अधिक हो रही हैं, जबकि विश्व स्तर पर लिंग आधारित हमले बढ़ रहे हैं। बच्चों के खिलाफ हिंसा सहित अंतर-वैयक्तिक हिंसा के विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव को भी अधिक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त हुई है। हिंसा के नए रूपों में फेमिसाइड और नैक्रोफीलिया, पेडोफीलिया जैसे मनोविकार वाली हिंसाएँ अपनी जड़ें जमा रही हैं।

क्या इस बात का भान है कि तकनीकी प्रगति ने घातक स्वायत्त हथियारों और साइबर हमलों, बॉट्स और ड्रोन के घातक हथियार से सुसज्जित झलकी और चरमपंथी हमलों की लाइवस्ट्रीमिंग के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं? डेटा हैक और रैंसमवेयर से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय सहयोग तनाव में है या तो अनचाहा सा है, जिससे सभी रूपों में संघर्ष और हिंसा की रोकथाम और समाधान के लिए वैश्विक क्षमता कम हुई है। यह है हिंसा का आलम। हिंसा के अभिवृद्धि से हम अभी आज जो चिंतित हैं, उसके 75 वर्ष बाद क्या प्रभाव होंगे, इस पर विचार आज की मांग है। इसलिए भी सन 2025 में कदम रखते हुए आज की सभ्यता को चौकन्ना होने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि तेजी से हम प्रकृति और मनुष्यता के समक्ष खड़ी हुई चुनौतियों को इस प्रकार से समाप्त करें जिससे आने वाला समय हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम भयभीत करने वाला न हो।

हम नए वर्ष का स्वागत कर लिए। नए उल्लास के साथ सबके मंगल की कामना करें, जो कि भारतीय रीति भी है लेकिन हमारा अब दायित्व यह आ गया है कि वर्ष 2025 में वर्ष 2100 वाली पीढ़ी के लिए अहिंसक, प्रेमपूर्ण, शांतिप्रिय, निर्भय, अर्थवान, प्रज्ञाशील, सहिष्णु एवं चिरंतन शांति से युक्त रोडमैप तैयार करें जिससे साभ्यातिक श्रेष्ठता आज हमें जतानी जो पड़ रही है, वह जतानी न पड़े बल्कि वह स्वतः सिद्ध हो। आज का समय देखकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी के लोग जताने में ज्यादा समय नष्ट कर रहे हैं, सृजन, प्रज्ञाशील वैचारिकी का वातावरण निर्मित करने में पिछड़ जाते हैं। इसलिए सम्यक दूरदृष्टि ही हमारे अहिंसक सभ्यता के निर्माण में सहयोगी साबित हो सकती है, इसे समझें और इसे अनुष्ठान के रूप में जीवन का हिस्सा बनायें ताकि स्वस्थ समाज और स्वस्थ भविष्य के हम निर्माता कहे जाएँ।

वो बागबां बिला शक औरों से अलग था...

स्मरण डॉ. मनमोहन सिंह

डॉ. सुधीर सक्सेना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

13 का अंक सारी दुनिया में अशुभ अंक के तौर पर ज्ञात और ख्यात है। इस मान से डॉ. मनमोहन सिंह ऐसी शख्सियत हैं; जिन्होंने तेरह के अंक को अलग महत्ता, द्युति और शुचिता प्रदान की। क्रमिक तौर पर डॉ. सिंह विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के तेरहवें प्रधानमंत्री थे। तरेह का अंक उन्हें ऐसा फला कि उनके सन् 2004 से सन 2009 के दरम्यानी पहले प्रधानमंत्रित्व काल ने उनके द्वितीय प्रधानमंत्रित्व काल का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह वह भारत के प्रथम और स्वप्नदृष्टा प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के उपरांत दूसरे ऐसे राजनेता हुये, जिसने पहले पूर्णकाल के बाद दूसरे पूर्णकाल के लिए इस पद पर बने रहने का गौरव अर्जित किया। वह पूरी एक दहाई इस महादेश के प्रधानमत्री रहे और विनम्रता, विद्वता और मितभाषिता के त्रिगुण से उन्होंने पंत प्रधान के पद को अपूर्व और विरल गरिमा प्रदान की। इसे समकाल का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि उनके इन मानवीय गुणों को लेकर उनके बड़बोले बैरियों ने उन पर तोहमतें मढ़ी और तंज कसे। लालकृष्ण आडवाणी की भांति डॉ. सिंह अविभक्त भारत में जनमे थे। उनका जन्म 26 सितंबर, सन 1932 को पंजाब में चमवाल के गांव गाह में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। पिता गुरूमुख और मां अमृत कौर की यह संतान बचपन से कुशाग्र बुद्धि थी। पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियों के बाद उन्होंने प्रतिष्ठित कैंब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड से डीफिल हासिल की। भारत लौटने पर उन्होंने अध्यापन को चुना। वह आर्थिकी की प्रतिभा थे और आर्थिकी में उसकी पैठ और दक्षता ने उन्हें सोपान पर सोपान मुहैया कर सर्वोच्च राजनीतिक आसन तक पहुंचाया। वस्तुतः डॉ. सिंह 'अ-पॉलिटिकल' शख्सियत थे। न उनके पास राजनीतिक विरसा था, न राजनीतिक कलायें और न ही राजनीतिक आकांक्षा। फिर भी वह प्रधानमंत्री बने; एक नहीं, दो बार बने। उनके मीडिया - सलाहकार संजय बारू ने उन्हें 'एक्सीडेंटल प्राइममिनिस्टर' की संज्ञा दी। यदि सादगी सौम्यता और मितभाषिता दुर्गुण है; तो वे दुर्गणी थे और यदि नहीं तो वे मानवीय गुणों से विभूषित ऐसे बिरल राज नेता थे, जो सत्ता के सर्पिल और रपटीले गलियारे मं दबे पांव चला। अपनी मितभाषिता से वह वाचाल नेताओं की भीड़ में अलग से चीन्हें गये, अलबत्ता मौनी बाबा कहकर उनका मखौल भी उड़ाया गया। पुरजोखिम राजनीति के बीहड़ में भी वह दबे पांव चलते रहे। छल-प्रपंच से दूर रहे। असहमति को ठौर दिया। पक्ष-विपक्ष के निदंक नियरे रखे।

विश्वव्यापी मंदी के दौर में उन्होंने देश की नाव को इस तरह खेया की चप्पुओं की आवाज न हुई और नौका पार घाट लग गयी। वह चुनावी राजनीति से सर्वथा दूर रहे। बस, एक बार चुनाव लड़ा। दक्षिण दिल्ली से लड़े और हारे तो किसी को अचरज न हुआ। जब वह वित्त मंत्री बने तो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। युक्ति के तहत वह असम से चुने जाकर राज्यसभा में पहुंचे। राज्यसभा यानि संसद का उच्च सदन। वह कम अर्सा गुरू (अध्यापक) रहे, लेकिन विद्वता से उपजा गुरूत्व उनमें ताउम्र कायम रहा। उनके कंधे दुर्बलता से नहीं, वरन दायित्वों से झुके रहे। उनकी गर्दन में कभी खम नहीं दिखे और लांछनों की तीखी बौछार में भी उनकी भृकुटि टेढ़ी न हुई। वस्तुतः वह भारत के उत्तर आधुनिक माल के नवाचारी और विजनरी पीएम थे। वित्त मंत्री भी नवाचारी थे; साहसिक नवाचारी। राजीव गांधी का प्रधानमंत्रित्व काल राजनीति से इतर संकायों की प्रतिभाओं को चीन्हने और एंगेज करने का काल था। सैम पित्रोदा से लेकर डॉ. मनमोहन तक। सन् 1985 में डॉ. सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाये गये। इस पद पर वह पांच साल रहे। इसी दशक में वह संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के सचिवालय में सलाहकार, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। सन 80 के दशक में उनके नाम से हमारी पीढ़ी की वाकफियत उन नोटों के जरिये हुई, जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की हैसियत से उनके हस्ताक्षर होते थे। इसमें शक नहीं कि आर्थिक मसौदों पर उनके दस्तख्त मानीखेज होते थे, और उन पर गौर किया जाता था। अपनी किताब 'इंडिया' ज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एण्ड प्रॉस्पेक्टस फॉर सेल्फ स्टेंड ग्रोथ' से वह दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों का ध्यान आकृष्ट कर चुके थे और उन्हें वैश्विक मान्यता मिली थी। केन्द्र सरकार के वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों में बतौर सलाहकार उनकी सेवायें लेने का सिलसिला सन् 70 की दहाई के शुरूआती वर्ष से ही शुरू हो गया था। 21वीं सदी की पहली दहाई में अमेरिका से न्यूक्लियर संधि उनके परिपक्व राजनय का परिणाम थी।

डॉ. सिंह को ऐसी सियासी शख्सियत माना जा सकता है जिसने प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब शायद ही कभी देखा हो। सियासत उनकी महत्वाकांक्षा का आसमान न था। बहरहाल, सच है कि समय अपना नायक स्वयं चुनता है। सन् 90 का दशक उनके लिये नेमते लेकर आया। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हाराव ने उन्हें वित्त मंत्री पद से नवाजा। पूरे पांच साल वह वित्त मंत्री रहे। वह बिना शोरशराबे या सियासी धौलधप्पे के कामों को अंजाम देते रहे। फलतः दुनिया ने उनका लोहा माना। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नजरों में वह चढ़े। देश की लद्धड़ इकोनामी पटरी पर आ गयी। उन्होंने वक्त के तकाजे को बूझा। युक्तियां आजमायीं। बंद दरवाजे खोले। वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण को तरजीह दी। नतीजे सामने थे। पहले राजीव गांधी और फिर नरसिम्हारव का भरोसा रंग लाया। नतीजे सामने थे। हाथ कंगन को आरसी क्या। डॉ. सिंह का नवाचार देश को फला। सन 2004 में बीजेपी का 'फील गुड' थोथा सिद्ध हुआ। डॉ. सिंह प्रधानमंत्री बने। पहले सिख प्रधानमंत्री। ऑपरेशन ब्लू स्टार और सिख विरोधी दंगों के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के दौर में उनका प्रधानमंत्री बनना मायने रखता था और उसके अपने निहितार्थ थे। प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार उन्हें सन 2002 में वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में मिला था और उन्हें पद्म विभूषण से सन 1987 में नवाजा जा चुका था। सन 1998 से सन 2004 तक वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी थे।

डॉ. सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल की बहुतेरी बातें लोगों को ज्ञात हैं। उन्हें दोहराने का औचित्य नहीं। इस दहाई में भारत ने वैश्विक मंदी का सामना बखूबी किया लेकिन इस काल में कुछेक दूरगामी महत्व के कानून पारित हुये। मनरेगा अस्तित्व में आया। सूचना का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। वनाधिकार अधिनियम/ कितनों को पता है कि सूचना के अधिकार में सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा राय और रोजगार गारंटी व भोजन अधिकार कानून में अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज से विमर्श की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रधानमंत्री रहते वह सात बार मध्यप्रदेश आये थे और साल 2011 में उनहोंने बीना रिफायनरी का शुभारंभ किया था। सन 2019 में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के विजन डॉक्यूमेंट का लोकार्पण भी किया था। भोपाल की मेट्रो परियोजना के पहले प्रस्ताव को मंजूरी उन्होंने दी थी। भोपाल में शामला हिल्स स्थित जनजातीय संग्रहालय का भी उन्होंने दौरा किया था। अभिभूत डॉ. सिंह ने विजिटर बुक में लिखा था - 'यह संग्रहालय नयी पीढ़ी को लोककला और संस्कृति की जानकारी देने का अदभुत स्थान है। संग्रहालय में संस्कृति और परंपरा का संगम देखने को मिला है। इसे बचाकर रखने की जरूरत है।'

मध्यप्रदेश का ही प्रसंग है। केन्द्र में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री थे। डॉ. सिंह प्रधानमंत्री एक साल पाले के कारण फसलों को गंभीर क्षति हुई। क्षतिपूर्ति की दस्तक पर केन्द्र सरकार का टके का उत्तर आया कि पाला प्राकृतिक आपदा की परिधि में नहीं आता। शिवराज हताश कि डॉ. सिंह का फोन आया। शिवराज दिल्ली पहुंचे। पीएम की पहल पर कमेटी बनी। उसमें प्रणब मुखर्जी थे, शरद पवार थे, पी. चिंदबरम थे और शिवराज भी। कमेटी ने पाले को प्राकृतिक आपदा मानने की संस्तुति की। फलतः मध्यप्रदेश को केन्द्र से 400 करोड़ रूपयों की मदद मिली। कन्नौज से एमएलए असीम अरूण मोदी सरकार में राज्यमंत्री है। पूर्व आईपीएस असीम 2004-07 में पीएम के बॉडीगार्ड रहे। पीएम हाउस में लकदक गाड़ियां थीं, मगर बकौल असीम डॉ. सिंह को पंसद थी अपनी मारूति 800। तो यकीनन डॉ. सिंह नामका शख्स औरों से अलग था। उसका पिंड अलग था। माली बदलने से चमन खाली नहीं होता, मगर जिसने 26 दिसंबर को 92 साल की वय में 'आंखें मूंदी' वह बागबां औरों से अलहदा था। उनके सिर झुकाकर चलने का शेर बार-बार यूं ही, उद्धृत नहीं हो रहा है। मीडिया को डॉ. मनमोहन सिंह नामक आडंबरच्युत व्यक्तित्व को आदरपूर्वक इसलिये भी याद रखना चाहिये कि, प्रधानमंत्रियों की खुली प्रेसवार्ताओं की श्रंखला में सन 2014 में अंतिम प्रेसवार्ता का श्रेय देश के तेरहवें प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के खाते में दर्ज है। जो दोबार ओपन हार्ट सर्जरी से गुजरा था। सच तो यह इस कलुष दौर में हमें अधिक से अधिक डॉ. मनमोहन चाहिये।

नवचेतना, नव-उन्मेष का रहे नव वर्ष

अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया

लेखक स्तंभकार हैं।

देखते ही देखते नए वर्ष ने हमारे जीवन में अपनी दस्तक दे दी है। हम सबके जीवन में कुछ नया या सुखद हुआ होगा, या कुछ ऐसी यादें होंगी, जिसे हम भूलना चाहेंगे। फिर भी पुरानी सिलवटों को ठीक करने का समय आ गया है। नया वर्ष मात्र एक सुबह नहीं बल्कि एक संदेशात्मक और नव उन्मेष की और बढ़ाने वाला हमारा पहला कदम भी हो सकता है, जिससे हम अपने आगामी हर वर्ष को सुखद एवमं सफल बना सकते है। जिस प्रकार नव का अर्थ नित्य या नया है और उन्मेष का अर्थ खिलना या नए विचारों का हमारे भीतर आना होता है।

इसी प्रकार हर वर्ष हमारे बीते वर्षों से आगामी वर्षों में कुछ नया करने का हमारा संकल्प भी हो सकता है। लेकिन हम हमेशा नए विचारों को नए वर्ष के उन संकल्पों की श्रेणी में खड़ा कर देते जिन्हें हम कभी पूरा करने वाले ही नहीं होते। तो फिर हम क्या करना चाहते है? क्या केवल बातों से ही हम अपने जीवन के बेहतरीन या यूँ कहें ही अनमोल वर्षों को बर्बाद कर देना चाहते। जिसके दुःख में हम अपने अंतिम क्षणों में खुद को ही दोषी साबित करते रहे।

आखिर हम कब अपने मानव जीवन का महत्व समझेंगे? कब हमें यह अहसास होगा कि जो कुछ भी है, वह आज ही है। बातों के महलों में वास्तविकता की दीवारों का निर्माण कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपनी वास्तविक धरातल की गहराई को समझते हुए, उस पर अपने भविष्य की सशक्त इमारत का निर्माण करना चाहिए। कोई दूसरा कभी भी हमारे जीवन का निर्णय नहीं ले सकता। हमें ही अपने जीवन को एक दिशा दिखानी होगी, जिससे हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में सहायता प्राप्त हो सकें।

जीवन के कुछ नियमों को अपने आगामी वर्षो का मित्र बनाकर हम अपने हर वर्ष को सुखमय कर सकते है। समय के महत्व को समझें - सबसे पहले हमें अपने जीवन में समय का महत्व को समझना ज़रूरी है। इस बात से हमें भली- भांति परिचित होना चाहिए। जिसने समय की कद्र नहीं कि समय फिर उसकी कद्र कभी नहीं करता। समय की पाबंदी को अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लेना चाहिए।

इसके अतिरिक्त अपने किए जाने वाले कार्यो की एक सूची तैयार करें जिससे आपको मदद मिल सके कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं।

अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए स्वयं को महत्व दें। दिन के कुछ क्षण अपनी सेहत को समर्पित करें, जिससे की आप स्वस्थ रह सके।

किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले उसके बारे में पढ़े और अपनों से वरिष्ठ लोगों की सलाह ले, जिससे की हमारे कार्यक्षेत्र में हमें लाभ मिल सकें। काम की दौड़भाग में अपने परिवार को समय देना ना भूलें।

हर दिन नई ऊर्जा से भरा होता है। ईश्वर ने हमें मानव जीवन देकर जो अनमोल उपहार दिया है, उसकी कद्र करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। हर क्षण नई उम्मीद के पौधे की खिलने में अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग ले। आप देखेंगे कि आपके कुछ ही कोशिशों से बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। बस जरूरत है तो अपने ही जीवन में अपने ही लिए कुछ सकारात्मकता लाने की।

आशा करती हूँ कि आगामी जीवन आपके लिए नवचेतना और नव-उन्मेष की सकारात्मक लहर को लेकर आए। जो आपके आने वाले हर वर्ष को सफल बनाने में सहयोगी हो सकें।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पी.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस प्रा. लि., राउखेड़ी, देवास रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 662, साईं कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक - उमेश त्रिवेदी
संपादक (म.प्र.) - गिरीश उपाध्याय
वरिष्ठ संपादक - अजय बोकिल
स्थानीय संपादक - हेमंत पाल
प्रबंध संपादक - अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

'तू खिलाड़ी मैं अनाड़ी' का नागिन डांस

व्यंग्य

प्रभुनाथ शुक्ल

लेखक व्यंग्यकार हैं।

जिंदगी में अगर जोश नहीं है फिर जीने का मतलब भी कुछ नहीं है। अलबत्ता यूँ कहें कि जिंदगी का दूसरा नाम जोश है। यह दीगर बात है कि हम कभी –कभी जोश में होश खो बैठते हैं। जहाँ हम होश खो बैठते हैं वहीं जिंदगी को हम जंग बना देते है। वैसे हमारे पास पड़ोस में ऐसे जोशीले लोग भरे पड़े हैं। जिनके जोश के आगे सर्कस के कलाबाज भी पानी भरते हैं। वह जिंदगी को बाजीगरी के रूप में देखते हैं। दरअसल ऐसे लोग असल जिंदगी में स्टंटमैन होते हैं। इनकी कलाबाजी के किस्से हमारी जिंदगी में आम होते हैं। घर से लेकर बाहर तक ऐसे स्टंटबाज देखने को मिल जाते हैं।

महानगरों में ऐसी फ़िरकी करने वालों की कमी नहीं है। चलती लोकल ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म पर ऐसे दौड़ते हैं जैसे वे खुद ही बुलेट ट्रेन हों। चलती रेल के डिब्बों से लटकते हुए गजब की कलाबाजी दिखाते है। ऐसी कलाबाजी तो हमने कभी सर्कस में भी नहीं देखी। सर्कस के कलाबाज अगर अपनी कलाबाजी दिखाते हैं तो सुरक्षा के लिए उपाय भी रखते हैं। मौत के कुएँ में कलाबाजी दिखाने वाला कलाकार गोले से बाहर कभी नहीं निकलता। शेर के पास खड़ा स्टंटमैन उसे कोड़े से नियंत्रित करता है। काफी ऊंचाई पर झूले का खेल दिखाने वाले कलाबाज बिना जाल के करतब नहीं दिखाते हैं। लेकिन हमारे आसपास बिखरे ऐसे कलाबाज वाकई कितने साहसी और खतरों के खिलाड़ी होते हैं। वे अपने को खिलाड़ी बाकि दुनिया और लोगों को अनाड़ी समझते हैं। हम उनकी कला के आगे सिर झुकाते है।

हमारे आसपास बिखरे इन कलाबाजों के बारे में मैं कभी – कभी गंभीर चिंतन करता हूँ। ऐसे प्रजाति के लोग की जन्म कुंडली देखता हूँ तो बड़े गतिशील होते हैं। इनकी कुंडली में ठहराव शब्द का सर्वथा अभाव रहता है। इनकी गतिशीलता कुम्हार के चाक से भी अधिक गतिमान होती है। इनके जीवन में एक और खासियत होती है यह स्टंटबाज के साथ –साथ सेल्फीबाज भी होते है। कभी पहाड़ों, डैम और सड़कों पर बाइक रेसिंग करते अपनी सेल्फी और वीडियो सोशलमीडिया पर डालकर लोगों में काफी लोकप्रिय भी हो जाते हैं।

खुली सड़कों पर रेसिंग करते ऐसे लोग खूब दिखते हैं। जाम में तो ऐसे स्टंटबाज नागिन डांस करते हैं। अपनी महंगी बाइक को नागिन जैसी नचाते हैं। अपने शरीर को भी लचीला छड़ बना लेते हैं। जैसे –जैसे बाइक नागिन डांस करती भीड़ से निकलती है वैसे –वैसे उनकी शरीर भी डांस करती है। ट्रेन आने के पहले रेलवे फाटक बंद हो जाता है, लेकिन इनकी जिंदगी इतनी गतिशील है कि ऐसे लोग फाटक खुलने का इंतजार भी नहीं करते हैं, बल्कि खुद नागिन डांस करते बंद रेल फाटक से क्रॉस कर जाते हैं। वह रेल कानून को भी अंगूठा दिखाते हैं। उनकी यह कलाबाजी आम लोगों को भी अच्छी लगती है, लेकिन अफ़सोस लोग ऐसा नागिन डांस कर नहीं पाते। कभी वह वक्त भी आता है जब इनकी कलाबाजी परिवार, समाज और खुद के लिए एक बुरे हादसे में तब्दील हो जाती है और खुद तस्वीरों में एक याद बन जाते है।

जयंती पर विशेष

अवनीश सोमकुवर
लेखक मप्र जनसंपर्क विभाग में उप संचालक हैं।

सावित्रीबाई फुले : विरोध और जागरूकता की कविता

भारतीय इतिहास के कुछ कालखंड ऐसे हैं जिन आज हम सिर्फ आश्चर्य और गर्व कर सकते हैं। जब हम माता सावित्रीबाई फुले का जीवन और उनका संघर्ष पढ़ते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि उनके जैसे महान व्यक्तित्व को हर क्षण याद रखने की जरूरत है। उनके जीवन का स्पष्ट संदेश है कि संसाधनों के अभाव से दृढ़ निश्चय और प्रतिबद्धता क्षण भर को परेशान हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं हो सकते।

सावित्रीबाई फुले को कभी भी अनजान नहीं रहना चाहिए। वे आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षक थीं, जिन्होंने 1846 में पुणे में भिड़े के वाड़े में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह ऐसा समय था जब लड़कियों को शिक्षा देना वर्जित था। बेटियों को पढ़ाने के लिए उनका संघर्ष कल्पना से परे है। उन्होंने उस्मान शेख के वाडे में वयस्कों और खेतिहर मजदूरों के लिए एक और स्कूल खोला। अपने समय से बहुत आगे की सोच रखने वाली सावित्री बाई फुले ने बेटियों की हत्या को रोकने के लिए अपने घर पर एक आश्रय स्थल शुरू किया। यहां विधवाएं सुरक्षित प्रसव कर सकती थीं।

ब्रिटिश शासन में भारत की आज़ादी के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता हासिल करने की प्रक्रिया एक साथ चल रही थी। ऐसा समाज जो अस्वस्थ परंपराओं, जातिवाद और निराधार अनुष्ठानों से बंधा हो वह ब्रिटिश शासन से कैसे लड़ सकता था। ऐसा विदेशी शासन जो समाज को बांटकर शासन करने में चतुर और सक्षम था। सावित्रीबाई फुले का जीवन हर जागरूक नागरिक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सातारा जिले के नायगांव में पैदा हुई थीं। उनका विवाह महान समाज सुधारक ज्योतिराव फुले से 1840 में हुआ। समाज सुधार के महान कार्यों के अलावा सावित्रीबाई फुले को हमेशा मराठी कविता की प्रर्वतक के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कविता के माध्यम से उन लोगों की बेहतरी के लिए आवाज उठाई, जो भेदभाव का शिकार होते थे। मराठी साहित्य के आधार स्तंभ केशव सुत को माना जाता है। इसी प्रकार आधुनिक हिंदी साहित्य का आधार स्तंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। यह तथ्य भी विचारणीय है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ और केशव सुत का साहित्य में आगमन 1901 में हुआ जबकि सावित्रीबाई फुले के दो सुगठित काव्य संग्रह 1854 और 1892 में आ चुके थे।

सावित्रीबाई फुले निस्संदेह आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षक थीं, लेकिन यह भी सच है कि वे विरोध और जागरूकता के स्वरों वाली पहली मराठी कवियित्री थीं। उनके नाम पर केवल दो काव्य संग्रह हैं। पहला संग्रह 'काव्यफुले' 1854 में प्रकाशित हुआ था, जब वे केवल 23 वर्ष की थीं। इसमें प्रकृति, सामाजिक मुद्दों और शिक्षा पर 41 कविताएं थीं। दूसरा संग्रह 'बावन काशी सुबोध रत्नाकर' 1892 में प्रकाशित हुआ।

विषयवस्तु और अभिव्यक्ति के मान से ये काव्य संग्रह कई काव्य ग्रंथों को पीछे छोड़ते हैं। इसका सीधा कारण यह है कि उनकी कविता उनके सकारात्मक कार्यों से प्रेरित थी। उनकी कविता का एक उद्देश्य था। लोगों को जागरूक करना। उन्हें नींद से जगाना। कविता में समाज सुधारक का व्यक्तित्व और प्रतिबद्धता स्पष्ट दिखते हैं। उनके काव्य में एक गहरी सामाजिक-आर्थिक जागरूकता और पीड़ा है। यह आनंद के लिए नहीं है, बल्कि यह एक आह्वान है।

इसलिए वे कहती हैं -
'विद्या हेच धन आहे रे,
श्रेष्ठ संया धनाहून
तीचा साथ जयापाशी
ज्ञानी तो मानती जन।'

इसका मतलब है - ज्ञान ही सभी का कीमती धन है। वही सबसे समृद्ध वे हैं, जो इसे प्राप्त करते हैं। वे अत्याचारियों से उबारने, अन्याय के प्रति जागने और मुक्ति पाने के लिए आक्रामक रूप से प्रेरित करती हैं। शिक्षा आवश्यक है ताकि खतरनाक विचारों के बंधन को तोड़ा जा सके।

'उठा बांधून अत्याचारणा, जागे होऊनी उठा,
परंपरेची गुलामी ही तोडने साठी उठा,
बांधून, शिकण्यासाठी उठा।'
(उठो, हे वंचितों। जागो और उठो।
परंपरा की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए उठो।
शिक्षा के लिए उठो।)'

सावित्रीबाई ने अंग्रेजी भाषा को भी सीखने की सलाह दी। उनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा ज्ञान के नए क्षितिज खोलती है और वंचित वर्गों को ज्ञान-आधारित समाज से जोड़ती है। वे अंग्रेजी को देवी के रूप में वर्णित करने में भी संकोच नहीं करतीं। इस प्रकार वह अपने समय से बहुत आगे थीं। वह कहती हैं-

'इंग्रजी माऊली, देई सत्य ज्ञान,
शूद्राला जीवन, देई प्रेम।
इंग्रजी माऊली, शूद्रानं पाणी पाजी,
संगोपण आजी करते।
इंग्रजी माऊली तोडते पशुत्व,
देई मानवत्व शूद्रलोक।'
(माँ अंग्रेजी, जो देती है सत्य का ज्ञान,
उन्हें सम्मानित जीवन देती है, प्रेम देती ह।
यह उन्हें पानी देती है, जैसे माँ करती है।
अंग्रेजी पशुत्व को नष्ट करती है और मानवता का उपहार देती है।)

सावित्रीबाई केवल उपदेश नहीं देतीं, बल्कि यह भी प्रश्न उठाती हैं कि यदि मनुष्य अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करता और शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद सीखने में असफल रहता है, तो उसे मनुष्य कैसे कहा जा सकता है। एक लंबी कविता में वह विस्तार से बताती हैं-

'त्यास मानव म्हणणे का?
ज्ञान नाही, विद्या नाही,
ते घेणें ची गोदी नाही,
बुद्धी असूनही चालत नाही।
त्यास मानव म्हणणे का?'
(क्या उन्हें मानव कहा जा सकता है?
ज्ञान और शिक्षा के बिना,
उन्हें प्राप्त करने की कोई चेष्टा नहीं,
और बुद्धि होने के बावजूद, वे नहीं चलते।
क्या उन्हें मानव कहा जा सकता है?)
'दुसऱ्यात मदत नाही,
सेवा त्याग दया माया नाही,
ज्यापाशी सद्गुण नाही,
त्यास मानव म्हणणे का?'
(जो दूसरों की मदद नहीं करते, सेवा, त्याग, दया, माया से वंचित हैं, जो सद्गुणों से रहित हैं, क्या उन्हें मानव कहा जा सकता है?)

सावित्री बाई फुले एक सजग, तर्कशील, भावप्राण, जुझारू क्रांतिकारी कवयित्री थीं। काव्य संग्रह 'काव्य फुले' में उन्होंने धर्म, धर्मशास्त्र, धार्मिक पाखंडो और कुरीतियों के खिलाफ निडर होकर लिखा। औरतों की सामाजिक स्थिति पर कविताएं लिखीं और उनकी बुरी स्थिति के लिए जिम्मेदार पितृसत्ता का विरोध किया। एक कविता में वे अज्ञानता को पहचान कर उसे पकड़कर कुचल-कुचल कर मारने के लिए कहती हैं, क्योंकि यह अज्ञानता ही स्त्री की दुश्मन है। वे कहती हैं -

'अज्ञानाची दाद्राची गुलागिरीही तोडू चला
युगयुगाचे जीवन आपले फेकून देऊ चला चला।'

यानी अज्ञानता और दरिद्रता की गुलामगिरी चलो तोड़ डालें। युगों का यह
दासता भरा जीवन चलो फेंक आएं।

सावित्री बाई ने प्लेग पीड़ित रोगियों की सेवा करते हुए 66 वर्ष की आयु में खुद भी प्लेग से पीडित हो गई और खुद को उत्सर्ग कर दिया। एक कविता में उन्होने लिखा है - 'आम्ही तयांचे वंशज रडगाणे नच गाणारे' यानी हम ऐसे लोगों के वंशज हैं जो अपने दुखों का रोना नहीं रोते और न ही अपनी व्यथा का प्रदर्शन करते हैं। हम रोनी सूरत वाले नहीं हैं।

मोदी सरकार

शिवेष प्रताप
लेखक जन नीतियों के विश्लेषक हैं।

मानसिक स्वास्थ्य को मुख्यधारा में लाने वाला क्रांतिकाल

3 दिसंबर 2024 को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने मानसिक स्वास्थ्य हेतु मोदी सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों के बारे में राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया। एक ऐसा विषय जिसने मोदी सरकार के इस प्रयास के बारे में बहुत जरूरी चर्चा को जन्म दिया है। मोदी युग ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करने और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को मुख्यधारा की स्वास्थ्य देखभाल नीतियों में एकीकृत करने पर अधिक ध्यान दिया गया। मोदी सरकार से पहले, भारत में मानसिक स्वास्थ्य को काफी हद तक नजरअंदाज किया गया था, और मानसिक बीमारियों को लेकर लोगों में एक शर्म और भ्रान्ति व्यापक था। हालाँकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साशन में, मानसिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में मान्यता देने की दिशा में बदलाव हुआ।

मानसिक स्वास्थ्य ऐतिहासिक रूप से भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य का सबसे उपेक्षित पहलू रहा है, जो संक्रामक रोगों और बुनियादी ढाँचे की कमियों की वजह से दबा हुआ था। भारत में मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत ही गलत समझा जाने वाला और कलंकित विषय बना हुआ था। लगभग 14 प्रतिशत भारतीयों को सक्रिय मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप की आवश्यकता होने के बावजूद, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16) में पाया गया कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले लगभग 80 प्रतिशत लोग सामाजिक कलंक, जागरूकता की कमी या देखभाल तक सीमित पहुँच के कारण मदद नहीं लेते हैं। यह कलंक सांस्कृतिक धारणाओं से उपजा है जो अक्सर मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को उपचार योग्य चिकित्सा समस्याओं के बजाय व्यक्तिगत कमज़ोरी या धार्मिक दोष के संकेत के रूप में देखते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ़ मानसिक बीमारी का न होना नहीं है; इसमें भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल है, जो व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। एक स्वस्थ दिमाग उत्पादक जीवन, सामंजस्यपूर्ण समाज और संपन्न अर्थव्यवस्था का आधार है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को अगर अनदेखा किया जाए, तो अपराध, बेरोज़गारी, मादक द्रव्यों के सेवन और कमज़ोर पारिवारिक व्यवस्था जैसी सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत जैसे देश के लिए, जो 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने की आकांक्षा रखता है, मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से त्रस्त आबादी के लिए नवाचार करना, प्रतिस्पर्धा करना और अपनी आर्थिक गति को बनाए रखना मुश्किल होगा। मानसिक स्वास्थ्य को राष्टीय सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में एकीकृत करना अनिवार्य है।

भारत एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत की लगभग 7.5 प्रतिशत आबादी मानसिक विकारों से पीड़ित है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16) से पता चला है कि लगभग 15 प्रतिशत भारतीय वयस्कों को सक्रिय मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है, मानसिक स्वास्थ्य ख़राब है और इसके लिए पर्याप्त धन नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि देश में प्रति 100,000 लोगों पर एक से भी कम मनोचिकित्सक हैं, जबकि डब्ल्यूएचओ ने प्रति 100,000 पर तीन मनोचिकित्सक होने की सिफारिश की है। भारत में मानसिक विकारों के लिए उपचार का अंतर 70-92 प्रतिशत के बीच है, और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान का अनुमान 2012 और 2030 के बीच 1.03 ट्रिलियन डॉलर है। ऐसे चौंकाने वाले आँकड़े मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करने के लिए मजबूत नीतियों और बुनियादी ढाँचे की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

मोदी के नेतृत्व में, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इसके निर्माण और परिचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था और मई 2018 में लागू हुआ था।

अधिनियम का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि यह मानसिक बीमारी को मानवाधिकार के मुद्दे के रूप में मान्यता देता है, यह सुनिश्चित करता है कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ बहिष्कृत जैसा व्यवहार न किया जाए, बल्कि वे कानून के तहत देखभाल, उपचार और सुरक्षा के हकदार हों। अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, मानसिक स्वास्थ्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत करके और यह सुनिश्चित करके कि सेवाएँ सभी स्तरों पर उपलब्ध हों। यह आत्महत्या के अपराधीकरण पर भी जोर देता है और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति एक दयालु, पुनर्वास दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। यह अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच के अधिकार को सुनिश्चित करता है, मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्डों की स्थापना को अनिवार्य बनाता है, तथा उपचार से पहले सूचित सहमति की गारंटी देता है, जिससे रोगियों को सशक्त बनाया जाता है। इसके अलावा, यह अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा और पेशेवरों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने का आह्वान करता है, जिससे अधिक सूचित और सहायक स्वास्थ्य सेवा वातावरण में योगदान मिलता है।

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल करना, जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने 1.73 लाख से अधिक उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सफलतापूर्वक अपग्रेड किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ जमीनी स्तर पर उपलब्ध हों।

ये केंद्र अब मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिसमें आउटपेशेंट परामर्श, मनो-सामाजिक हस्तक्षेप, मूल्यांकन, परामर्श, निरंतर देखभाल और आवश्यक दवाओं तक पहुँच शामिल है। यह दृष्टिकोण मानसिक बीमारियों का शीघ्र पता लगाना और उनका प्रबंधन सुनिश्चित करता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कलंक और बाधाओं को कम किया जा सकता है।

ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रोकर्स द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि 46 प्रतिशत भारतीय फर्मों का मानना है कि उन्हें अपने कर्मचारियों के लिए बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता है। यह मान्यता बढ़ते अस्पताल बिलों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आई है, जो राजस्व वृद्धि और वेतन वृद्धि से कहीं ज़्यादा है, जिससे व्यवसायों के लिए वित्तीय चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। आगे के शोध से पता चलता है कि भारत में कार्यस्थल पर तनाव अक्सर लंबे समय तक काम करने, खराब कार्य-जीवन संतुलन और सामाजिक और पेशेवर अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक आत्म-लगाए गए दबाव से प्रेरित होता है। मोदी सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली नीतियों के माध्यम से कार्यस्थलों में मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

मानसिक स्वास्थ्य के प्रति मोदी सरकार का बहुआयामी दृष्टिकोण एक स्वस्थ और अधिक उत्पादक भारत के लिए मजबूत नींव रख रहा है। प्रमुख परिणामों में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और टेली-मानस के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक बेहतर पहुंच, कलंक को कम करने और प्रारंभिक हस्तक्षेप को बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में मानसिक स्वास्थ्य को एकीकृत करना और उपचार की कमी को पाटने के लिए कुशल मानसिक स्वास्थ्य कार्यबल का विकास शामिल है। हालांकि, मानसिक बीमारियों के लिए महत्वपूर्ण उपचार अंतर और सामाजिक कलंक जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं, जो कई लोगों को मदद लेने से रोकती हैं। इनसे निपटने के लिए, सरकार को पहल का विस्तार करना, जागरूकता अभियान बढ़ाना और अधिक समावेशी मानसिक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना जारी रखना चाहिए।

जयंती पर विशेष

चित्रा माली
प्रभारी,अकादमिक निदेशक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता।

सावित्री बाई फुले : आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका

'स्त्रियां केवल घर और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी हैं, वह पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती हैं'। सावित्री बाई फुले जब यह बात कह और लिख रही थीं, उस समय इस प्रकार प्रतिकार करना सामान्य नहीं था, खासकर किसी महिला का और वो भी दलित महिला के द्वारा किया जाना,यह अपने आप में महत्वपूर्ण था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस क्रांतिकारी पृष्ठभूमि का निर्माण ज्योतिबा फुले लगातार कर रहे थे। जिस प्रकार इतिहास लेखन में महिलाओं को तवज्जो या कहें उनके स्थान को गौण रखा गया है उसी प्रकार दलितों को भी उनके कार्यों और योगदान को भी नजरअंदाज करने की लगातार कोशिश की गई है। लेकिन उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सभी ग़ैर-ब्राह्मण जातियों को एक अस्मिता और रेडिकल विचारधारा के तहत लामबंद करने की कोशिश की। फुले ने रामदास द्वारा प्रचारित महाराष्ट्र धर्म का नाम नहीं लिया लेकिन महाराष्ट्र धर्म के मूर्त प्रतीक शिवाजी के राज्य को शूद्रों के राज्य के रूप में गर्व से याद करते हुए शिवाजी को 'कुनबी कुलभूषण' कहा। फुले द्वारा शिवाजी को 'कुनबी कुलभूषण' कहना अत्यंत अर्थपूर्ण था और वे ब्राह्मणों द्वारा तैयार वंशावली को भी नकार रहे थे। इसके लिए फुले ने तीन महत्वपूर्ण स्थापनाएं दी। सबसे पहले उन्होंने सत्रहवीं सदी के उस पूरे दृश्य से मुसलमान को अगर पूरी तरह से हटाया नहीं तो उसे गौण करने का कार्य अवश्य किया। मुसलमानों को गौण कर देने का मतलब मुसलमानों की उस तथाकथित धर्मनाशी भूमिका को खारिज कर देना था जिसकी ब्राह्मण सबसे ज्यादा दुहाई देते थे। उन्होंने स्थापित किया कि समाज का मुख्य अंतर्विरोध मुसलमान और हिंदू के बीच नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था और व्यापक ग़ैर-ब्राह्मण आवाम (मुख्यतः दलित- शूद्रों) के बीच है। इसके बाद फुले ने शिवाजी के मराठा राज्य के साथ ब्राह्मण वर्ग के इस बहुप्रचारित संबंध को खारिज किया कि एक ब्राह्मण रामदास शिवाजी के गुरु थे और मराठा राज्य क़ायम होने का मुख्य श्रेय रामदास के उपदेशों को ही मिलना चाहिए। फुले के नेतृत्व में महाराष्ट्रीयन नवजागरण की ग़ैर-ब्राह्मण धारा ने ब्राह्मणों,सुधारकों और परंपरानिष्ठों से समाज,संस्कृति और इतिहास के हर मुद्दे पर लोहा लेने का कार्य किया। इस ब्राह्मणवादी निर्मित समाज व्यवस्था को जानने और समझने के लिए आवश्यक था कि हर व्यक्ति शिक्षित हो जिसका प्रयास ज्योतिबा फुले के द्वारा किए गए और आधी आबादी को शिक्षित करने का जिम्मा उन्होंने अपनी अर्धांगनी सावित्री बाई फुले को सौंप दिया। सावित्री बाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव नयागांव में 3 जनवरी 1831 में हुआ था। सावित्री बाई फुले के परिवार के द्वारा उनकी आरंभिक शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी क्योंकि उस समय महिलाओं और दलितों को शिक्षित होने का कोई अधिकार नहीं था। महज 9 वर्ष की आयु में ही वे ज्योतिबा फुले से ब्याह दी गई थी। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले का जब विवाह हुआ तब ज्योतिबा तीसरी कक्षा में पढ़ते थे। ज्योतिबा फुले ने सावित्री बाई में शिक्षा के प्रति अनुराग को देखते हुए उन्हें पढ़ाना शुरू किया। सावित्रीबाई फुले ने भी शिक्षा के महत्व और अनिवार्यता को समझा और महिलाओं और बालिकाओं के लिए शिक्षा को सरल और सहज बनाने की मुहिम में अपने पति के साथ हो गई। भारत में स्त्री शिक्षा या बालिका शिक्षा का औपचारिक इतिहास देखा जाए तो 1830 में पुणे के शनिवार वाडे में एक विद्यालय चलाया जाता था जहां सात से आठ बालिकाएं अध्ययन करती थीं जो प्रिविलेज तबके की थीं उन्हीं की शिक्षा के लिए यह विद्यालय चलाया जाता था। इसके बाद बंगाल में 1847 में नबीनकृष्ण मित्रा और कालीकृष्ण मित्रा ने बारासात (वर्तमान का 24 परगना) में एक प्राइवेट स्कूल खोला था। प्रारंभ में दो ही बालिकाओं ने प्रवेश लिया था जिनमें से एक नबीनकृष्ण मित्रा की बेटी कुंतीबाला थी। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले सिंथिया फैरार से अत्यंत प्रभावित हुए जो बोस्टन शहर से भारत आई थीं और तमाम विरोधों के बाद भी बॉम्बे के स्कूल में अनोखे तरीके से बालिकाओं को पढ़ा रही थीं। 1848 में पुणे के बुधवार पेठ में सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने डिप्रेस्ड क्लास के बच्चों के लिए एक विद्यालय आरंभ किया।

सावित्रीबाई फुले इसकी प्रथम शिक्षिका बनी। 3 जुलाई 1857 को फुले दंपति ने पहले बालिका विद्यालय का शुभारंभ किया था। स्त्री शिक्षा के विरोध में एक प्रिविलेज तबका था जो नहीं चाहता था कि महिलाएं और बालिकाएं शिक्षित हों तथा महिलाओं की सामाजिक हैसियत में कोई बदलाव आए, वहीं विद्यालय के लिए जमीन देने वाले और सहयोग करने वालों की भी कमी नहीं थी। पहले बालिका विद्यालय की जमीन अन्ना साहब चिपलूणकर जी के द्वारा दी गई थी जो प्रिविलेज तबके से होने के बावजूद भी फुले दंपत्ति का सहयोग कर रहे थे। दूसरे विद्यालय के लिए जमीन फातिमा शेख ने उपलब्ध करवाई तथा शिक्षिका की जिम्मेदारी का निर्वहन भी किया। सावित्रीबाई फुले जब अपने घर से बालिकाओं को पढ़ाने के लिए विद्यालय जाती थीं तब उन पर कचरा,गोबर,विष्ठा व पत्थर भी फेंके जाते थे, वे अपने साथ एक थैली में दूसरी साड़ी भी रखती थीं जिसे विद्यालय में बदलकर अध्यापन का कार्य करती थी। इससे हम सभी परिचित हैं। तमाम विरोधों और अवरोधों के बाद भी सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों के अधिकारों और शिक्षा के लिए प्रयास जारी रखे। वैश्विक पटल पर भी महिलाओं की शिक्षा को लेकर काफी कुछ लिखा जा रहा था। 'ए विंडीकेशन ऑफ राइट ऑफ वूमन' जो मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने 1792 किताब लिखी थी और उसमें महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया था और साथ ही शिक्षा में सुधार,सार्वजनिक और निजी शिक्षा को मिला देना,एक अधिक लोकतांत्रिक, भागीदारी के शैक्षणिक ढांचे पर भी चर्चा की है। इसी तरह जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1869 में 'द सब्जेक्शन ऑफ वूमन' निबंध में भी महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया है इसी के साथ लिंग समानता,पति -पत्नी के बीच सच्चे एवं पवित्र रिश्ते,आदर्श विवाह,स्त्री-पुरूष के बीच संबंधों में भी सुधार के विषय में भी ध्यानाकर्षित किया है। इन सभी विचारों को जहां हम अंतरराष्ट्रीय फलक पर देख रहे थे वहीं इसके समानांतर भारत में फुले दंपत्ति के द्वारा भी शिक्षा को लेकर खासकर महिलाओं की शिक्षा को लेकर व स्त्री पुरुष समानता व अंधविश्वासों व कर्मकांडों से मुक्ति के प्रयास तथा सामाजिक कुरीतियां बाल विवाह,जाति प्रथा,समाज व्यवस्था,छुआछूत, पर्दा प्रथा के विरुद्ध भी संघर्ष किए जा रहे थे।

शूद्रों/दलितों को न्याय दिलाने के लिए फुले दंपति ने 1873 में ''सत्यशोधक समाज'' की स्थापना की, जिससे लोगों में फैले अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों और जातिप्रथा को समाप्त किया जा सके। अछूतों के लिए जलाशय की व्यवस्था की, मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा किसानों और श्रमिकों को जागरूक करने का कार्य भी सत्यशोधक समाज के बैनर तले किया गया तथा इनको शिक्षित करने के लिए विद्यालय भी खोले गए। फुले दम्पति ने कई विधवाओं के विवाह करवाए तथा एक विधवा महिला के बच्चे को दत्तक लेकर उस महिला का विवाह भी करवाया। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं को समाज के उत्पीड़न से बचाने के लिए घरों का निर्माण और बच्चों के लिए अनाथ आश्रमों का निर्माण भी किया। सावित्री बाई फुले को आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है उन्होंने प्रकृति,शिक्षा और जातिप्रथा को केंद्र में रखकर अधिकतर कविताएं लिखी वो भी उस दौर में जब जातिप्रथा अपने चरम पर थी। इसी के साथ उन्होंने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा भी दिया। महाराष्ट्र में वर्गीय चेतना के अधिक होने से यहां हुए सुधार कार्यक्रमों और सुधारकों को जानने व उनके सम्मान की एक अलग परंपरा है। सावित्रीबाई फुले की जन्मतिथि को राजस्थान में 'शिक्षिका दिवस' के रूप में मनाया जाता है। जिससे महिलाओं की शिक्षा को लेकर सजगता का भी बोध होता है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में इस दिन को 'बालिका दिवस' के रूप में मनाया जाता है। सावित्री बाई फुले की जन्मतिथि व पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रमों में उनके द्वारा प्रतिपादित सुधारवादी कार्यक्रमों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है और उनको वर्तमान समय में लागू करने के प्रयास करना भी आवश्यक हैं। जिससे अंधविश्वासों, कर्मकांडों, जातिवाद और गैर बराबरी को समाप्त कर समतामूलक समाज की स्थापना की जा सके जो तर्क पर आधारित विज्ञानपरक हो। एक ऐसे समाज का निर्माण किया जा सके जिसकी नींव सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले ने रखी थी।

नववर्ष पर साईं भक्तों ने किया खिचड़ी प्रसाद वितरण

बैतूल/भौरा। नववर्ष के उपलक्ष्य में बुधवार को नगर के बस स्टैंड एवं सीमेंट रोड पर साईं भक्तों द्वारा खिचड़ी प्रसाद का वितरण

किया गया। आयोजन में नगरवासियों सहित सैकड़ों बाहर से आए लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। साईं भक्तों ने बस स्टैंड पर साईं बाबा का छायाचित्र स्थापित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सर्वप्रथम साईं बाबा की पूजा-अर्चना की गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने सामूहिक प्रार्थना करते हुए सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। इसके बाद खिचड़ी प्रसाद का वितरण शुरू किया गया।

इस अवसर पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। नगर और आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन साईं भक्तों के सामूहिक प्रयासों से किया गया, जिसमें भक्तों ने अपनी सेवा और समर्पण का परिचय दिया। साई सेवा समिति के सदस्यों के ने बताया कि यह आयोजन हर वर्ष नववर्ष पर किया जाता है। उन्होंने कहा, साईं बाबा की कृपा से हमें यह सेवा करने का अवसर मिला है। हम चाहते हैं कि यह प्रसाद लोगों के जीवन में सुख और शांति लाए। इस प्रकार के आयोजनों ने नगर में आपसी सौहार्द और भक्ति की भावना को बढ़ावा दिया है। श्रद्धालुओं ने साईं बाबा से नववर्ष में सुखद भविष्य और स्वास्थ्य की कामना की।

बीजासेन दरबार में 255वी महाआरती संपन्न

बैतूल/ भौरा। ग्राम भौरा बीजासेन दरबार में इन दिनों भक्ति रस बरस रहा हैद्य ग्रामीणों द्वारा प्रतिदिन सुबह और शाम आरती के गाए स्वर, भौरा की गलियों में सुनाई देते है द्य जयमातादी मंडल भौरा एवं ग्रामवासियो की आस्था का केंद्र बने बीजासेन दरबार में महाआरती की परंपरा निर्बाध रूप से निरंतर चली आ रही हैद्य जयमातादी मंडल के राजा मालवीय ने बताया कि माँ बीजासेन प्रांगण में 255वी महाआरती का आयोजन किया गया था, जिसमे विशाल संख्या में भक्तो ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई द्य माँ बीजासेन के पावन महाआरती महोत्सव में आरती के पश्चात प्रसाद वितरण का कार्यक्रम संपन्न किया गया द्य उल्लेखनीय है कि ग्राम के आस्था का केंद्र माँ बीजासेन धाम में सुबह- शाम हो रही आरती के स्वर से सारा ग्राम भक्ति रस में सराबोर हो जाता है द्य ग्रामीण भी सुबह और शाम की बेला में निर्बाध रूप से आरती के लिए मंदिर प्रांगण में एकत्रित हो जाते है द्य ग्रामवासी बताते है कि आरती में शामिल होकर मन सात्विक शांति प्राप्त करता है द्य हम सारा दिन कही भी रहे, मगर आरती के लिए सभी मंदिर प्रांगण में एकत्रित होकर माता रानी के श्री चरणों में अरदास लगाते है द्य कुछ लोगो से शुरू हुए इस आयोजन में अब एक विशाल संख्या का समूह बन गया है द्य मंगलवार होने वाली महाआरती में युवा, बालक और ग्राम के वरिष्ठ नागरिक सभी शामिल होते है द्य प्रसाद वितरण के पश्चात सुमधुर संगीत से सुसज्जित भजन, माता की भेंट से उत्पन्न भक्ति रस में सभी श्रद्धालू साराबोर हो जाते है द्य

बस यात्री महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील देवास पुलिस

देवास/मोहन वर्मा। देवास पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के निर्देश पर यातायात पुलिस देवास द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों एवं संकटकालिन स्थिती में क्या करे,क्या न करे? के संबंध में जागरूक्ता करने हेतु इंदौर-देवास मार्ग पर चलने वाली यात्री बसों में जाकर महिला यात्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया ।

पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा महिलाओं से संवाद कर उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या या खतरे की स्थिति में त्वरित सहायता के लिए डायल 100,महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 के संबंध में भी जानकारी दी गई । इस विशेष अभियान का उद्देश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और आत्मरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना है । देवास पुलिस की यह पहल समाज में महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है ।

ईको फ्रेंडली अतिक्रमण मुक्त हॉकर्स जोन जागरूकता अभियान

देवास। नगर निगम आयुक्त रजनीश कसेरा के निर्देशानुशार शहर को प्लास्टिक मुक्त व अतिक्रमण मुक्त बनाना है, साथ ही जो हाथ ठेले वाले अव्यवस्थित तरीके से सड़कों पर यातायात एवं आवागमन को बाधित करते हैं, उनके लिए हॉकर्स जोन की सुविधा निगम द्वारा मुहेया कराई जा रही है साथ ही शहर के प्रमुख चौपाटी को डिस्पोजल व अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा। बुधवार 1 जनवरी को सहायक स्वास्थ्य अधिकारी भूषण पवार, स्वच्छ भारत मिशन से अरुण तोमर एवं निगम की सहयोगी संस्था बेसिक्स के टीम लीडर अंकित पाल एवं सुपरवाएजर द्वारा एवं निगम कर्मचारियों के साथ बीमा चौराहा स्थित चौपाटी (हॉकर्स जोन) को व्यवस्थित करवाकर चाट ठेले वाले से 2 डस्टबिन का प्रयोग एवं नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथिन के स्थान पर पर्यावरण हितैषी सामग्री का प्रयोग करने की अपील की। जीरो वेस्ट अतिक्रमण मुक्त हॉकर्स जोन से उद्देश्य यह है कि जो हाथ ठेले शहर में अव्यवस्थित रूप से इधर-उधर घूमते हैं, जिनके कारण यातायात व्यवस्था के साथ-साथ आवागमन भी बाधित होता है। इसके लिए फुटकर व्यापारियों की सुविधा के लिए ही स्थल चयन करके हॉकर्स जोन बनाया गया है जहां डिस्पोजल फ्री ईको फ्रेंडली सुविधायुक्त चौपाटी रहे इस हेतु निरंतर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे है।

निगम कार्यालय में हुआ राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रगान

देवास। शासन द्वारा प्रतिमाह के प्रथम कार्य दिवस पर शासकीय कार्यालयों मे राष्ट्रगीत वन्देमातरम एवं राष्ट्रगान जन गण मण गायन किये जाने के निर्देश हैं। दिनांक 1 जनवरी 25 तक राष्ट्रीय शोक हेने से शासन के पत्र क्रमांक एफ-5-7/2005/1-4 भोपाल दिनांक 31-12-24 अनुसार गुरूवार 2 जनवरी 25 को राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान किये जाने के निर्देश पर निगम कार्यालय मे निगम उपायुक्त देवबाला पिपलोनिया के द्वारा निगम अधिकारियों व कर्मचारियों को गुरूवार 2 जनवरी को निगम परिसर मे राष्ट्रगीत वन्देमातरम एवं राष्ट्रगान जन गण मण गायन के साथ गायन किया गया। इस अवसर पर कार्यालय अधिक्षक अशोक देशमुख, विशाल जगताप, विकास शर्मा, ब्रजमोहन सराठे, हेमराज सांगते, संजय पारखे, अजीमुद्दीन शेख, सतीष मेवाती, निर्मल कुशवाह, हेमन्त शिन्दे, शेलेष जनवासिया, मुजफ्फर अली, मोईज अंसारी, अविनाश देशपांडे, मुकेश सोलंकी, शमशुद्दीन शेख, ललीता चौहान, दिपीका मजूमदार, वहीदा शेख, अंजुम शेख आदि सहित निगम कर्मचारी उपस्थित रहे।

7 करोड़ के दो अंडरपास तो बनवाए, परंतु लोगों की परेशानी कम होने की बजाय बढ़ी

● जहां सबसे ज्यादा थी जरूरत, वहां अब बढ़ी लोगों की परेशानी

वाहन चालकों को दिन में 120 बार बंद गेट का करना पड़ रहा सामना

संजय द्विवेदी, बैतूल। शहर के सोनाघाटी से कोसमी क्षेत्र के बीच में एक किमी में रेलवे फटकों को बंद करके दो अंडरब्रिज सात करोड़ की लागत से रेल्वे ने बना दिए थे, परंतु जिस हनुमान मंदिर के नीचे की रेलवे क्रॉसिंग के गेट पर सबसे ज्यादा ट्रैफि क रहता है, वहां दिन में 120 बार गेट बंद होने से दोनों ओर पॉलिटेक्निक छात्रों के साथ आस-पास के ग्रामीणों की लंबी कतार लग जाती है। वहां इसके बगल में बनाए गए अंडरपास को भी इसके रास्ते पर स्थित कुएं के धंसकने के खतरे को देखते हुए रेल्वे ने हाल ही में बंद कर दिया है जिससे अब लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ट्रेन के आने और जाने के समय और इसके आसपास के समय में घंटों का इंतजार करना पड़ता है। यदि वाहन चालक को जल्दी हो तो फि र उसे फ ोरलेन के रास्ते तीन किमी का लम्बा फेरा लगाकर ही दूसरी ओर पहुंचना पड़ता हैं। यहां पर किसी तरह का अंडरपास नहीं बनाया गया है। सोनाघाटी के पहले चंद खेतों तक जाने वाली जगह पर एक रेलवे क्रॉसिंग का गेट था। इस गेट क्रमांक 254 को भी बंद करके इसकी जगह पर 3 करोड़ की लागत से अंडरब्रिज बना दिया गया है। जबकि यहां से एक घंटे में 10 वाहन भी नहीं गुजरते हैं। हालांकि हाल ही में एक बड़ी कॉलोनी जरूर यहां डेवलप की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि रेल्वे के 3 करोड़ के इस खर्चे का लाभ सिर्फ इस कॉलोनी की ब्रांडिंग और यहां के ग्राहकों को लुभाने के लिए हो रहा है। इसी तरह 4 करोड़ का कोसमी औद्योगिक क्षेत्र का गेट नंबर-255 भी बंद करके इसकी जगह पर अंडरब्रिज बना दिया गया है। हालांकि यहां थोड़ा ट्रैफि क रहता है।

फाटक बंद होने से 9 साल से परेशान लोग-पुराने बैल बाजार के रेलवे गेट, जिसे वर्ष 2015 में बंद कर दिया गया था, वहां पर भी परेशानी हो रही है। यहां पर ओवरब्रिज के नीचे का रेलवे क्रॉसिंग का गेट खर्च ज्यादा होने का हवाला देकर वर्ष 2015 में रेल्वे ने बंद कर दिया था लेकिन अभी तक अंडर ब्रिज नहीं बनाया है। यहां से वाहन चालक 2 किलोमीटर का फेरा लगाकर ब्रिज के ऊपर से दूसरी ओर जाते हैं। ओवरब्रिज की भी स्थिति जगह-जगह गड्डे होने से खराब है, 9 सालों से वाहन चालक यहां पर परेशान हो रहे हैं।

पॉलिटेक्निक कॉलेज, मंडईबुजुर्ग, झगड़िया जाने वाले वाहन चालक परेशान

एक तरफ लगाए सीमेंट के टुकड़े, दूसरी तरफ लोहे का बैरियर

सोनाघाटी के हनुमान मंदिर के नीचे रेलवे क्रॉसिंग का गेट क्रमांक 253 है। यह गेट दिन में सामान्यतया 120 बार खुलता और बंद होता है। इस गेट के बंद रहने के कारण इसके ठीक बगल में स्थित छोटे अंडरपास से पॉलिटेक्निक कॉलेज, मंडईबुजुर्ग, झगड़िया और झाड़ेगांव आदि गांवों में जाने वाले वाहन चालक आसानी से इस अंडरपास से गुजरते थे। दरअसल इस अंडरपास के नजदीक पर ही एक कुआं है, जिसके आसपास के चारों ओर की जमीन धंसक रही है। इस साल बहुत ज्यादा बारिश हुई है, कुआं ज्यादा बारिश होने पर उपर तक भर गया, वजन पडने् पर यहां की पूरी जमीन धंसक सकती है। इसीलिए एहतियात के तौर पर किसी को भी नुकसान से बचाने के लिए, इस कुएं के आसपास कंटीली झाड़ियां डाल दी है। कुएं की मुंडेर के अगल-बगल की जमीन धंसकने के कारण कंटीली झाड़ियां लगाकर उस अंडरपास को हाल ही में बंद कर दिया गया है। इस प्रकार अंडरपास के रास्ते को भी दोनों ओर से सीमेंट के टुकड़े और लोहे के बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है। गुरुवार दोपहर को यह गेट बमुश्किल चंद मिनटों के लिए खुला रहा। ट्रेन निकलने और ट्रेन नहीं होने के बाद भी 15-15 मिनट से अधिक समय तक यह गेट बंद रहा और लोग परेशान होते रहे।

ट्रेन व्हीकल यूनिट की गणना की जरूरत- किसी भी जगह पर किसी अंडरपास या अंडरब्रिज बनाने के पहले ट्रेन व्हीकल यूनिट यहां कैलकुलेशन करती है,

अंडरपास के नजदीक कुएं की मुंडेर के अगल-बगल की जमीन धंसकने के कारण कंटीली झाड़ियां लगाकर किया बंद

रेल्वे उपनी ओर से गणनाएं करवाती है। इस तरह की गणना यहां पर करवाने की जरूरत है। जिससे वाहनों की वास्तविक संख्या, सभी जगह सामने आ सके।

एडीईएन का ऑफिशियल मोबाइल नंबर नहीं होता रिसीव, कार्यप्रणाली पर उठे सवाल- इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी एडीईएन सोनल बेशेकर के ऑफ ीशियल मोबाइल नंबर पर फ ोन किया तो लगातार कई कॉल लगाए जाने के बावजूद उन्होंने आफि शियल मोबाइल नंबर रिसीव नहीं किया, ना ही कोई कॉल बैक किया, यह पहला अवसर नहीं है इसके पहले भी इसी तरह की कार्यप्रणाली उनकी रही है। जब हमने नागपुर रेल मंडल पीआरओ यश जनबंधु को फ ोन किया, तो उन्होंने भी इस पर आश्चर्य जताया कि ऑफि शियल नंबर तो किसी भी तरह की सूचना देने के लिए कोई भी उपयोग कर सकता है। कोई जरूरी सूचना रहीं, तो यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। उन्होंने इस संबंध में संबंधित एडीईएन से बात करने का आश्वासन भी दिया।

इनका कहना

लोगों को परेशानी न हो ऐसी व्यवस्था के होंगे प्रयास -

- जिस रेलवे क्रॉसिंग और गेट की आप बात कर रहे हैं, वहां की जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली जाएगी। इस बारे में नियमानुसार क्या हो सकता है, देखा जाएगा। वाहन चालकों को परेशानी नहीं हो, इसकी व्यवस्था बनाने का प्रयास जल्द से जल्द किया जाएगा।

- यश जनबंधु,
पीआरओ रेल मंडल नागपुर

विधायक के प्रयास से भौरा में खुलेगा बिजली ऑफिस, 70 गांवों को होगा फायदा

बैतूल/ भौरा। क्षेत्रीय विधायक गंगा सज्जन सिंह उईके के सतत प्रयासों से भौरा में जल्द ही एक नया बिजली वितरण केंद्र (बिजली ऑफिस) स्थापित होने जा रहा है। इस केंद्र के खुलने से भौरा और आसपास के 70 गांवों के हजारों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। यह कार्यालय स्थानीय स्तर पर बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान करेगा, जिससे उपभोक्ताओं को अब शाहपुर या अन्य दूरस्थ केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

विधायक का प्रयास लाया रंग- लंबे समय से भौरा और आसपास के गांवों के उपभोक्ता बिजली समस्याओं के समाधान के लिए दूर-दराज के कार्यालयों का रुख करने को मजबूर थे। इसे देखते हुए विधायक श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उईके ने इस मामले को प्राथमिकता पर लिया और विद्युत विभाग के अधिकारियों से लगातार संवाद कर यह सुनिश्चित किया कि भौरा में एक बिजली ऑफिस खोला जाए। इस संबंध में विधायक उईके ने कहा, भौरा में बिजली कार्यालय खुलने से क्षेत्रीय जनता को बड़ी राहत मिलेगी। यहां के लोगों को उनकी बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। यह विकास क्षेत्र के लोगों को समर्पित है।

70 गांवों के हजारों उपभोक्ताओं को राहत- भौरा में खुलने वाला यह नया वितरण केंद्र 70 गांवों की सेवा करेगा। इसमें डाबरी,

बीजादेही, ढोढरामोहार, फोफलिया, टांगना, सोनादेह, हांडीपानी, बानाबेहड़ा चीखल्दा, कछार, चिलमटेकरी, और आसपास के गांव शामिल हैं। स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि यह कदम समय और संसाधनों की बचत करेगा।

इस संबंध में शाहपुर वितरण केंद्र के सहायक यंत्री (एई) गोविंद राव डोंगरे ने कहा, भौरा में बिजली ऑफिस खुलने से स्थानीय उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने, बिल संबंधी समस्याओं और अन्य मुद्दों का समाधान अब उनके निकट ही उपलब्ध होगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि नए कार्यालय में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों और लोगों को समय पर सेवाएं मिलें।

स्थानीय उपभोक्ताओं में खुशी- भौरा के स्थानीय निवासी इस फैसले से बेहद खुश हैं। डबरी गांव के रामलाल यादव ने कहा, पहले हमें 40 किलोमीटर दूर शाहपुर जाना पड़ता था, जिससे हमारा समय और पैसा दोनों बर्बाद होता था। अब बिजली ऑफिस पास में होगा, जिससे हमें बड़ी राहत मिलेगी। वहीं, भौरा निवासी जय किशोर मिश्रा ने कहा, हर बार छोटी समस्या के लिए दूर जाना मुश्किल होता था। अब हमें यहीं समाधान मिल जाएगा। यह विधायक का एक बड़ा कदम है। नए बिजली ऑफिस में प्रारंभिक तौर पर शिकायत निवारण, बिल सुधार और नई कनेक्शन की सुविधाएं दी जाएंगी। जो उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान करेंगे।

झल्लार थाने अंतर्गत फलफूल रहा जुआ का कारोबार

बैतूल । बैतूल एसपी निश्चल एन. झारिया के सख्त निर्देशों के चलते लगातार जिले में चल रहे जुए और सट्टे के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है, इसके बावजूद कुछ थाने क्षेत्र ऐसे हैं, जहां लगातार जुए-सट्टे का खेल अपनी चरम सीमा पर है । ताजी जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय के नजदीक झल्लार थाना के अंतर्गत और मुलताई थाना क्षेत्र में जुआ का अवैध कारोबार जमकर फल फूल रहा है ।

मिली जानकारी के मुताबिक झल्लार थाना क्षेत्र में सुनील और प्रदीप की जोड़ी इस गोरखधंधे के जाल में झल्लार सहित आसपास के ग्रामीणों के साथ-साथ पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के लोगों को फंसा लिए हैं । झल्लार के सुनील उर्फ कल्लू और कोलगांव के प्रदीप स्थानीय पुलिस को चकमा देकर बेहद होशियारी के साथ जगह बदल-बदल कर 52 पत्ती के खेल को बड़े पैमाने पर अंजाम दे रहे हैं । सूत्र के अनुसार यहां बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के जुआरी पहुंच रहे हैं जिससे क्षेत्रवासियों में कोई बड़ी घटना की अंदेशा के चलते भय और दहशत का वातावरण निर्मित हो रहा है। इसी तरह मुलताई थाना क्षेत्र के प्रभातपट्टन पुलिस चौकी अंतर्गत मंगोनाकला के पास कर्णपुर में ताईखेड़ा के पिंटू और आष्टा पत्तन के साहब राव भी वृहद पैमाने पर जुआ का फड़ संचालित कर रहे हैं । इनके हौसले इतने बुलंद है कि वे जुआरियों के लिए टेंट, लाइट और भोजन पानी की व्यवस्था भी करते हैं । साथ ही पुलिस की आमदी से बचने के लिए जुए अड्डे के चारों तरफ खंती खोद कर रख दिए हैं ताकि पुलिस वाले आसानी से यहां नहीं पहुंच पाए। बताया गया कि जिनके खेतों में जुए का अड्डा संचालित किया जा रहा है वह किसान इसकी शिकायत बैतूल कलेक्टर और एसपी सहित जनप्रतिनिधियों को कर रहे हैं।

इनका कहना

ताप्ती नदी के किनारे कुछ लोग जुआ चला रहे हैं और कुछ खेल रहे हैं, इसकी सूचना हमें मिली है। लेकिन अगर बड़ी संख्या में लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं और बड़े पैमाने पर जुआ खेला जा रहा हैं तो मै आज ही दिखवाता हूं, जुआरियों पर निश्चित ही कार्रवाई होगी ।

-मनोज उइके, टी आई थाना झल्लार

डॉ.गोठी ने जिला चिकित्सालय में अंकुरित आहार वितरण के लिए डोनेट किए 11 हजार

बैतूल। बॉलीवुड के फिल्म निर्माता बैतूल निवासी अक्षय गोठी और सिने व्यवसाई अमित गोठी के पिता डॉ. अनिल गोठी 1 जनवरी को अपने जन्म दिवस और नया वर्ष के उपलक्ष्य में जिला चिकित्सालय में दशकों से संचालित हो रहे अंकुरित आहार वितरण के लिए रुपए 11000 की राशि डोनेट किया है। उक्त राशि से जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन सुबह अंकुरित आहार वितरण करने वालों के अनुसार लगभग एक वर्ष तक डॉ गोठी की ओर से अंकुरित आहार मरीज और मरीजों की परिजनों को वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही जिला अस्पताल कैंपस में मरीज और उनके परिजनों के लिए भोजनशाला संचालित है वहां भी डॉक्टर गोठी की ओर से 1 जनवरी को मरीजों और उनके परिजनों को भोजन कराया। गौरतलब है कि डॉ अनिल गोठी का जन्मदिन का अवसर उस समय यादगार साबित हुआ जब बैतूल नगर पालिका के रिटायर्ड ऑडिटर बंटी वासनिक अपने मित्रों के साथ डॉ. गोठी के पास उनके निवास पहुंचकर फूल माला पहनकर जन्मदिन की बधाइयां दी और उन्हें उनके स्वस्थ और लंबी जीवन के लिए कामना की। इस दौरान श्री वासनिक के साथ मुख्य रूप से एडवेंचर शौकीन नौशा खान, कृष्णा पांसे, रवि ज्ञानचंदानी आदि मौजूद थे।

जल कलश पूजन के साथ प्रारंभ हुई ताप्ती संपूर्ण परिक्रमा पदयात्रा

तीन प्रदेश 180 किलोमीटर का सफर 64 दिन में तय करेंगे पदयात्री

बैतूल/मुलताई। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मां ताप्ती का संदेश लेकर मां ताप्ती संपूर्ण परिक्रमा पदयात्रा का प्रारंभ किया गया। संपूर्ण ताप्ती परिक्रमा यात्रा का प्रारंभ ताप्ती तट मां ताप्ती मंदिर मुलताई में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और ताप्ती सरोवर कुंड की परिक्रमा के साथ हुआ, धार्मिक रीति रिवाज के साथ जलकलश का पूजन कर परिक्रमा पदयात्रा का श्रीगणेश किया। जगह-जगह ताप्ती यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया नगर वासियों ने ताप्ती परिक्रमा यात्रियों पर पुष्प वर्षा की, घरों के सामने रंगोली डाली गई, घरों के सामने स्वागत द्वार सजाए गए। ताप्ती परिक्रमा यात्रा का प्रथम पड़ाव मेरी माता मंदिर पर सभी ताप्ती यात्रियों का भाव स्वागत किया गया। इस अवसर पर परिक्रमा यात्रा में शामिल लोगों ने बताया कि संपूर्ण प्रति परिक्रमा यात्रा का उद्देश्य ताप्ती का संदेश लोगों तक पहुंचता है और ताप्ती के

प्रति लोगों में जागृति पैदा करना है ताप्ती यात्रा के माध्यम से मां ताप्ती की कृति जन-जन तक पहुंची है और बड़ी संख्या में लोग इस पदयात्रा से जुड़ रहे हैं यह संपूर्ण ताप्ती परिक्रमा यात्रा तीन प्रदेशों को सुख और समृद्धि का वरदान देने वाली मा ताप्ती उद्गम स्थल से निकालकर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एवं गुजरात ताप्ती से समुद्र संगम स्थल सूरत तक कुल 1800 किलोमीटर का पैदल सफर 64 दिन में पूर्ण करेंगी। परिक्रमा पदयात्रा के संयोजक राजू पाटनकर ने बताया कि इस वर्ष ताप्ती यात्रा दक्षिण तट से नदी के समीप पदयात्रा करते हुए सूरत समुद्र संगम डुम्मस तक पहुंचकर वापस हजीरा से प्रारंभ होकर 5 मार्च को मुलताई उद्गम स्थल पर पहुंच कर सम्पूर्ण परिक्रमा पदयात्रा का समापन होगा।

कार्यालय नगर परिषद शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.)

क्र. / न. परि. / राज/2025/1194 Email:-cmoshahpur@mpurban.gov.in शाहपुर दिनांक: 01/01/2025

-:: निविदा विज्ञप्ति ::-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद शाहपुर मे श्री श्री 1008 मनसुखदास बाबा मेला वर्ष 2025 दिनांक 13-01-2025 से 27-01-2025 तक आयोजित किया जाना है, जिसमे प्लाट फीस वसूली का कार्य ऑफलाइन पर दिया जाना है।

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत रू.	अमानत राशि रू.	ठेकेदार
1	नगर परिषद शाहपुर मे श्री श्री 1008 मनसुखदास बाबा मेला हेतु प्लाट वसूली व्यवस्था कार्य।	2.20 लाख	3000/-	निविदाकर्ता का जी.एस.टी./ होना अनिवार्य है।

टीप :- निविदा से संबंधित शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।

1. फार्म लेने की तिथि	01.01.2025	10:30 PM
2. फार्म लेने एवं दर दिये जाने की अंतिम तिथि	07.01.2025	17:30 PM
3. प्रपत्र, इत्यादि का लिफाफा ए खोलने की तिथि	09.01.2025	10.30 AM

श्री श्री 1008 मनसुखदास बाबा मेला मे आयोजित कार्यक्रमो प्लाट वसूली करने हेतु निर्धारित शर्तें

01. नीलामी स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर परिषद शाहपुर के पास होगा।
02. नीलामी निविदा मे सफल ठेकेदार को नीलामी निविदा राशि का 05 प्रतिशत अतिरिक्त परफार्मेंस गारंटी के रूप मे तत्काल जमा करना होगा। जो ठेका अवधि समाप्त होने के पश्चात वापस की जावेगी ।
03. नीलामी निविदा स्वीकृत होने पर सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर स्वीकृत संपूर्ण नीलामी राशि जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा जमा राशि राजसात की जावेगी।
04. मेला प्लाट वसूली के लिये नीलामी की सरकारी बोली कर लिफाफे मे बढ़ते क्रम मे मान्य होगी।
05. शासकीय नीलामी बोली से कम बोली लगाई जाने पर मान्य नहीं की जावेगी।
06. स्वीकृत ठेकेदार अपना ठेका किसी अन्य ठेकेदार को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।
07. प्लाट/भूमि किराया 4 /- प्रति वर्गफीट लिया जावेगा।
08. प्रतिदिन की विशेष वसूली नगर परिषद शाहपुर द्वारा की जावेगी ।
09. मेला अवधि मे 02 साप्ताहिक बाजार दिवस (बुधवार) की वसूली नगर परिषद शाहपुर द्वारा की जावेगी ।
10. निविदाकर्ताओ के सफल बोली नहीं होने पर नगर परिषद शाहपुर द्वारा की जावेगी ।

अरूण कुमार श्रीवास्तव
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, शाहपुर

ताई से मिले पटवारी, यूका का कचरा डिस्पोज पर हुई चर्चा

बोले-रामकी में कचरा जलाने से इंदौर, धार व पीथमपुर के क्षेत्रों में पड़ेगा असर

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने आज इंदौर की पूर्व सांसद, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, ताई से मुलाकात कर पीथमपुर के रामकी कंपनी में डंप किये गये यूनियन कार्बाइड के कचरे इंदौर, धार, पीथमपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में पड़ने वाले दुष्प्रभाव को लेकर गहन चर्चा की।

श्री पटवारी ने कहा कि उक्त कचरा जलाने को लेकर कोर्ट के आदेश है, सरकार ने पीतमपुर की एक रामकी कंपनी में जो कचरा भेजा है जो रात में डंप हो चुका है, इसका इंदौर शहर पर क्या असर पड़ेगा बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है। श्री पटवारी ने कहा कि इस मुद्दों को राजनीतिक रूप देने से वाजिब नहीं है, इससे इंदौर सहित अन्य क्षेत्रों की जनता के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ताई से इस संबंध में बात हुई इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए। कुछ साल पहले रामकी में 10 टन कचरा जलाया गया था, जिसका असर लंबे क्षेत्रफल पर पढ़ा था। उन्होंने कहा कि यदि निरीक्षण करेंगे तो पता चलेगा कि जो फसल 5 क्विंटल होती थी वह घटकर एक क्विंटल ही रह गई है। सवाल यह है कि इतना कचरा जलेगा या डिस्पोजल होगा या वैज्ञानिक विधि से इसका डिस्पोजल होगा तो स्वाभाविक है यशवंत सागर तालाब जो वहां से 27 किलोमीटर दूर है, जब तालाब के पानी का रिसाव होगा तो उसका असर कितना पड़ेगा, यशवंत सागर का पानी दूषित होगा।

श्री पटवारी ने कहा कि कचरा जलाने के लिए जो एक्सपर्ट है, उनसे बात करके जब तक है क्लियर नहीं होगा, तब तक कचरा नहीं जलाना चाहिए, मेरा सभी से आग्रह किया है कि कचरा जलाने की योजना को थोड़ा अभी रोका जाये, विपक्ष के नाते हमारा दायित्व है कि हम जनता के प्रति अपने दायित्व निभाएं। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि एक एक्सपर्ट की टीम बनानी चाहिए, कचरा जलाने से इसका क्या असर होगा इस पर चर्चा होना चाहिए।

श्री पटवारी ने कहा कि 2020 में कोरोना आया था किसी को पता नहीं चला, लेकिन इसका कितना असर हुआ, हजारों, लाखों लोग हमारे परिवार के बीच से चले गए। फिर हम कचरा जलाने का रिस्क क्यों लें, प्रीतमपुर और धार में इसका विरोध हो रहा है। मीडिया जगत के साथियों से आग्रह है कि आप लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले, यह राजनीतिक हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस कचरे के निष्पादन का निर्धारण करके लोगों को समझाना आपका दायित्व है। जब तक यह कचरा डिस्पोजल की प्रक्रिया चालू नहीं हो आपने जो कचरा दम किया है, वह प्रक्रिया गलत है। कचरा डिस्पोजल हो गया तो आने वाली जनरेशन उससे प्रभावित होगी, उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। कैंसर का खतरा बढ़ेगा। प्रदेष के नगरीय प्रषासन मंत्री भी इंदौर के ही है, उन्हें भी इस बात की चिंता व्यक्त करते हुये लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट के आदेष हैं लेकिन यह आदेष नहीं है कि कचरा यहीं डंप होना चाहिए।

प्रेमी ने ही पीट-पीटकर की थी महिला की हत्या

साथ रहने की कर रही थी जिद, जमुनिया के जंगल में मिला था शव

छिंदवाड़ा (नप्र)। दो दिन पहले जमुनिया के जंगल में एक महिला का शव पड़ा मिला था। बुधवार को पुलिस ने मामले का खुलासा किया। महिला की हत्या उसके प्रेमी ने ही लाठी-डंडे से पीट-पीटकर की थी। महिला का शव जंगल में फेंककर उसका मोबाइल लेकर भाग गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला अमरवाड़ा थाना के ग्राम जमुनिया का है। अमरवाड़ा टीआई राजेंद्र धुर्वे ने बताया कि 30 दिसंबर को जमुनिया के जंगल में एक महिला मृत अवस्था में मिली थी, जिसके सिर में चोट के निशान थे, उसकी शिनाख्त जमुनिया निवासी विनीता पति सिनोद धुर्वे (39) के रूप में हुई थी। मृतका के पास से मोबाइल फोन गायब था, जिसके आधार पर पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि गांव में रहने वाले संतोष यादव के साथ प्रेम संबंध था। महिला अंतिम बार भी उसी के साथ देखी गयी थी, संदेह के आधार पर संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने हत्या की वारदात को कबूल कर लिया।

5 साल से थे अवैध संबंध

दरअसल, मृतिका अपने पति को छोड़कर रह रही थी। 5 साल से वह संतोष यादव के साथ में प्रेम संबंध में थी। आरोपी का कहना था कि विनीता उसे अपने साथ रहने का दबाव बना रही थी, जिसके कारण उसने उसे जंगल बुलाया लकड़ी से मारपीट कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को साड़ी से ढककर मृतिका का मोबाइल साथ में लेकर वहां से भाग गया। आरोपी संतोष यादव पिता भैयालाल यादव उम्र 42 साल निवासी ग्राम जमुनिया चौकी सिंगोडी थाना अमरवाडा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से घटना में प्रयुक्त लकड़ी और मृतिका का मोबाइल जब्त किया है।

हेलमेट उतारकर दोस्त को दिया, ट्रक की टक्कर से मौत

पचमढ़ी में नया साल मनाकर भोपाल लौट रहे थे दोनों, पीछे बैठे साथी को मामूली चोट

पिपरिया (नप्र)। पचमढ़ी में नया साल मनाकर भोपाल लौट रहे बुलेट सवार दो दोस्तों को सांडिया के पास एक ट्रक ने टक्कर मार दिया। हादसे में बुलेट चला रहे युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे युवक को मामूली चोट आई है।

मंगलवारा थाना एएसआई गणेश राय ने बताया कि हादसा बुधवार रात करीब 7.30 बजे पिपरिया से 22 किमी दूर सांडिया में हुआ। मृत युवक का नाम प्रमोद गुर्जर था। उसकी उम्र 42 साल थी। वह नरसिंहपुर

जिले के गाडरवारा थाना क्षेत्र (देवरी) का रहने वाला था और भोपाल रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था।

वहीं पीछे बैठा 34 वर्षीय युवक रवि चौरसिया मूलतः दमोह का रहने वाला है। वह इंदौर में रहकर पीएससी की तैयारी कर रहा था। रवि ने पुलिस को बताया कि दोनों नया साल मनाने के लिए पचमढ़ी गए थे। वहां से भोपाल लौट रहे थे। प्रमोद बुलेट चला रहा था।

हादसे से पहले उतार दिया था हेलमेट- रवि ने बताया कि दोनों की दोस्ती 2017 में दिल्ली में हुई थी। रवि का कहना है कि प्रमोद ने पचमढ़ी से चलते समय हेलमेट पहने रखा था। पिपरिया से कुछ दूर चलने पर उसने हेलमेट उतार कर उसे दे दिया। इसके कुछ देर बाद हादसा हो गया।

पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने सभी दो पहिया वाहन चालकों से हेलमेट एवं चार पहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने की अपील की है।

विद्यार्थियों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि वर्ष 2024-25 के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार सभी पात्र नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता एवं प्रवेश प्रक्रिया को 15 जनवरी तक पूर्ण किया जाए। साथ ही, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया को समयावधि में पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निवास कार्यालय में मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की और कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि कि 31 दिसंबर 2024 से काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जो 14 जनवरी 2025 को संपन्न की जाएगी। सभी शासकीय एवं अशासकीय नर्सिंग कॉलेजों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था लागू की गयी है। संचालक लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (नर्सिंग एवं पैरामेडिकल) श्री मनोज सरियाम, रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउसिंग श्री के.के. रावत सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पिता की डांट से नाराज किशोर फांसी पर झूला

पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा

भोपाल (नप्र)। पिता की डांट से नाराज किशोर के फांसी लगाने की घटना सामने आई है। घटना बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात की है, जब 17 वर्षीय किशोर करीब 2 बजे घर पहुंचा। जिसके बाद पिता ने डांट भी लगाई, तब किशोर ने दूसरे कमरे में जाकर फांसी लगा ली। जिसकी सूचना रात करीब 2:30 बजे पुलिस को दी, पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमॉर्टम हमीदिया अस्पताल में करवाया। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है, वहीं संबंधितों के बयान भी लिए जा रहे हैं।

देर रात पहुंचा था घर

एएसआई अनंत कुमार पांडे के अनुसार वाजपेयी नगर ईदगाह हिल्स इलाके में रहने वाले एक किशोर (17) रात करीब 2 बजे घर पहुंचा, जिसके बाद पिता ने उसे डांट लगाई, पूछा कि कहां से आ रहे हो, वहीं परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उससे इस बात को लेकर पूछताछ की, जिससे वह बुरी तरह से नाराज हो गया और दूसरे कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लिया।

वहां रखी एक साड़ी से फांसी का फंदा बनाया और फांसी पर झूल गया। बता दें कि किशोर के पिता मजदूरी करते हैं, लंबे समय से किशोर घर में देर रात ही आता था।

संविदाकर्मियों का बेमुद्दत धरना दूसरे दिन भी जारी

भोपाल। कंपकंपाने वाली ठंड के बावजूद संविदा कर्मियों का बेमुद्दत धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारी अपनी बीवी-बच्चों सहित धरने पर बैठे हैं, जिससे उनके संघर्ष और दृढ़ता का स्पष्ट उदाहरण मिलता है।

धरना स्थल पर संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से तुरंत समाधान की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि उनकी वर्षों की मेहनत और सेवा को नजरअंदाज किया जा रहा है, और अब इस उपेक्षा के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी हो गया है।

संविदा कर्मियों ने इस आंदोलन को अपने अधिकारों की लड़ाई करार देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक यह धरना जारी रहेगा।

धरने में बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी, उनके परिवार और अन्य समर्थन करने वाले लोग शामिल हो रहे हैं। ठंड के बावजूद उनकी हिम्मत और संघर्ष भावना देखते ही बनती है।

82 मोबाइल बरामद, फरियादियों को किए वापस

भोपाल। सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुम हुये 82 मोबाईल कीमती करीबन 25,00,000/- रूपये का मशरूका बरामद कर नव वर्ष में जोन-2 डीसीपी द्वारा फरियादियों को वापस दिया गया, साथ ही 132 मोबाईल कीमती 35,00,000/- का जोन 2 के सभी थानो से फरियादियों को वापस कर दिया गया है।

भोपाल शहर में सम्पत्ति संबंधी अपराधों पर नियंत्रण रखने के मामलों में मुखबिर तंत्र विकसित कर शत प्रतिशत बरामदगी सुनिश्चित करने पुलिस आयुक्त नगरीय भोपाल श्री हरिनारायणाचारी मिश्र, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल श्री अवधेश गोस्वामी द्वारा निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त जोन - 02 भोपाल श्री संजय अग्रवाल, अति.पुलिस उपायुक्त जोन-02 श्री महावीर मुजाल्दे व सहायक पुलिस आयुक्त मिसरोद श्री डॉ. रजनीश कश्यप, ण एमपीनगर अक्षय चौधरी, सहायक पुलिस आयुक्त गोविन्दपुरा दीपक नायक के मार्गदर्शन मे सभी थाना प्रभारी जोन 2 के द्वारा टीम गठित कर 80 मोबाइल बरामद करने मे सफलता अर्जित की हैं।

घटना व पुलिस कार्यवाही-थाना क्षेत्र मे विभिन्न स्थानों पर विभिन्न तारीखों में गुम हुये मोबाइलों के आवेदकों द्वारा थाने पर मोबाइल गुमने के संबंध में आवेदन पेश किये। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम द्वारा उक्त गुम हुये मोबाइलों को तत्काल पुलिस सायबर पोर्टल सीईआईआर पर सर्चिंग हेतु डाला गया। सर्चिंग के दौरान मोबाइलों के अपडेट जानकारी प्राप्त कर विभिन्न नम्बरों को ट्रैक कर 216 मोबाइल कीमती 60,00,000/- का बरामद किये गये। जिसमे जोन-2 के सभी थाने 132 मोबाईल कीमत 35,00,000/- का वापस कर दिये गये है। नव वर्ष में डीसीपी जोन-2 के माध्यम से 82 मोबाईल कीमत 25,00,000/- का फरियादियों को नववर्ष के शुभकामनों के साथ वापस दिया गया। समस्त थानों से सायबर सेल में लगे अधिकारी व कर्मचारी के सतत प्रयास यह संभव हुआ।

1.	बागसेवनिया	25	30
2	मिसरोद	05	42
3	गोविन्दपुरा	21	10
4	अयोध्या नगर	08	08
5	कटारा	02	06
6	पिपलानी	09	09
7	एमपीनगर	06	10
8	अरेरा	05	09
9	अवधपुरी	01	10

पूर्व में आवेदकों को दिए गए मोबाइल 134

एम्स भोपाल की अगस्त 2022 से अक्टूबर 2024 तक की प्रगति और उपलब्धियां, स्थापना और विकास

भोपाल। पीएमएसएसवाई के तहत अगस्त 2003 में स्थापित एम्स भोपाल को जुलाई 2012 में स्वायत्त दर्जा प्राप्त हुआ। इसकी आधारशिला 20 जनवरी 2004 को रखी गई थी। यह रिपोर्ट अगस्त 2022 से अक्टूबर 2024 तक की प्रगति का विवरण देती है।

शैक्षिक उपलब्धियां

एम्स भोपाल में विभिन्न कार्यक्रमों में छात्रों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है-

- एमबीबीएसः 125 छात्रों प्रति वर्ष (2022-2024) में निरंतरता।
- बीएससी (ऑनर्स): 75 से बढ़कर 90 छात्रों (20 प्रतिशत वृद्धि)।
- एमडी/एमएसः 103 से बढ़कर 165 छात्रों (28.9 प्रतिशत वृद्धि)।
- डीएम/एमसीएचः 30 से बढ़कर 75 छात्रों (134.38 प्रतिशत वृद्धि)।
- एमएससीः 28 से बढ़कर 42 छात्रों (40 प्रतिशत वृद्धि)।
- पीएचडीः उतार-चढ़ाव के बावजूद 2022 से 2024 तक 15 प्रतिशत वृद्धि।
- इंटर्नशिपः 2022-23 में शुरुआत, 2023 से 2024 तक 72.73 प्रतिशत वृद्धि।
- नए विभाग (2 वर्ष): 4 (मेडिकल जेनेटिक्स, रुमेटोलॉजी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी और इम्यूनोजेनेटिक्स)।
- नए उत्कृष्टता केंद्र (2 वर्ष): 4 (हैप्पीनेस सेंटर, प्रिसिजन मेडिसिन सेंटर, दुर्लभ रोगों में उत्कृष्टता केंद्र, हीमोग्लोबिनोपैथी केंद्र)।
- नए डीएम/एमसीएच कार्यक्रम (2 वर्ष): 22 विभिन्न विशेषज्ञताओं में।
- नए एसआर लिंक्ड फेलोशिप (2 वर्ष): 34, जिनमें अस्पताल प्रबंधन में मास्टर, एमएससी ट्रांसलेशनल मेडिसिन आदि शामिल हैं।
- नए मास्टर कार्यक्रम (2 वर्ष): 5।
- नए बैचलर कार्यक्रम (2 वर्ष): 10, जिनमें विभिन्न पैरामेडिकल क्षेत्रों को कवर किया गया है।

सहयोग

एम्स भोपाल ने प्रमुख संस्थाओं जैसे आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटीस, आईआईएसईआर भोपाल, आईआईएम इंदौर आदि के साथ 30 से अधिक सहयोग और समझौता ज्ञापन किए हैं।

पुस्तकालय संसाधन

पुस्तकालय ने अपने ई-संसाधनों में महत्वपूर्ण विस्तार किया है, जिसमें ई-बुक्स, ई-जर्नल्स और डेटाबेस शामिल हैं। विशेष रूप से, हिंदी चिकित्सा पुस्तकों का समावेश किया गया है और वैज्ञानिक लेखन के लिए ग्राम्मरली जैसी नई सेवाओं की शुरुआत की गई है।

रोगी देखभाल में वृद्धि

एम्स भोपाल ने रोगी देखभाल सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि देखी है-

- आउट पेशेंट (ओपीडी): 2021-22 में 22,392 से बढ़कर 2023-24 में 58,762।
- इन पेशेंट (आईपीडी): 2021-22 में 5,995 से बढ़कर 2023-24 में 11,547।
- बड़ी सर्जरीः 2021-22 में 4,868 से बढ़कर 2023-24 में 18,156।
- छोटी सर्जरीः 2021-22 से 2023-24 तक 179 प्रतिशत वृद्धि।
- जांच (लेब): 2021-22 में 135,510 से बढ़कर 2023-24 में 251,494।
- जांच (इमेजिंग): 2021-22 से 2023-24 तक 167 प्रतिशत वृद्धि।
- रोगी बेडः वर्चुअल बेड में वृद्धि, 0 से बढ़कर 195 (2 वर्षों में)।
- ट्रॉमा और इमरजेंसी (टीईएम) फूटफॉलः 2021-22 में 3,792 से बढ़कर 2023-24 में 10,454।
- आयुष्मान लाभार्थीः 2023-24 में रूपये 42.72 करोड़ से अधिक के दावे।

डिजिटल पहलें

एम्स भोपाल ने रोगी देखभाल में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पहलों की शुरुआत की है-

- जल्दी पंजीकरणः वेबसाइट, ऐप और कियोस्क का उपयोग कर पंजीकरण में 458 प्रतिशत की वृद्धि (2022-24)।
- आभा आईडी लिंकेजः 0 से बढ़कर 172,389 (2 वर्षों में)।
- स्कैन और शेयरः 0 से बढ़कर 501,721 (2 वर्षों में)।
- एम्स स्वास्थ ऐपः रोगी अनुभव में सुधार, प्रतीक्षा समय में कमी, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया।
- डिजिटल इंडियाः डिजिटल रोगी इंटरएक्शन में महत्वपूर्ण वृद्धि।

अनुसंधान और नवाचार

एम्स भोपाल ने अनुसंधान और नवाचार में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है-

- पबमेड प्रकाशनः पबमेड प्रकाशनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
- बाह्य अनुदानः कुल 257 अनुदान (पूर्ण और चालू), 2023-24 में 18.58 करोड़ रुपये से अधिक की राशि।
- आंतरिक अनुदानः छात्रों, रेसिडेंट्स और संकाय को दिए जाने वाले आंतरिक अनुदानों में उल्लेखनीय वृद्धि।
- दायर/अनुदानित पेटेंटः दायर और स्वीकृत पेटेंटों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- कॉपीराइटः कॉपीराइट के आवेदन और अनुदान में वृद्धि।
- स्नातक अनुसंधान फोरम (यूजीआरएफ): स्नातक छात्रों के बीच अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली एक अनूठी पहल, जिसके परिणामस्वरूप सम्मेलनों और अनुदान आवेदनों में भागीदारी बढ़ रही है।

प्रत्यारोपण कार्यक्रमः एम्स भोपाल ने अंग प्रत्यारोपण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है:

- गुर्दा प्रत्यारोपणः 3 जीवित-रिश्तेदार प्रत्यारोपण और पहला मृत-दाता प्रत्यारोपण किया गया।
- हड्डी मज्जा प्रत्यारोपण (बीएमटी): 7 बीएमटीस किए गए, जिनमें से 4 मरीज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं।
- हृदय प्रत्यारोपणः अक्टूबर 2024 में एसओटीटीओ निरीक्षण पूरा, जल्द ही स्वीकृति की उम्मीद है।

नवोन्मेषी प्रथाएं- एम्स भोपाल ने रोगी-केंद्रित नवोन्मेषी पहलों को लागू किया है-

- प्रशामक देखभाल के लिए एमएसएसओ।
- क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ' डेस्क और कर्मचारी।
- फार्मेसी और लैब रनर।
- ऑनलाइन पंजीकरण के लिए स्वयंसेवक।
- एनजीओ की भागीदारी।
- मल्टिपल रिविजिट और बिलिंग काउंटर।
- एम्स स्वास्थ्य ऐप।
- नो रिफ्यूजल पालिसी।
- मानव दूध बैंकः 481 लाभार्थियों को 363,321 मिली दूध एकत्र करके पिलाया गया।
- कॉर्निया दानकर्ताओं के लिए ग्रीन कार्ड।
- निःशुल्क वाई-फाई क्षेत्र (पीएम-वाणी)।
- कैंसर रोगियों के लिए ब्रैकीथेरेपी।
- बुनियादी ढांचे का विकासः बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश।
- चल रही परियोजनाएँ: प्रशासनिक ब्लॉक, आवासीय क्वार्टर, क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक और भूमिगत पार्किंग।
- नई सुविधाएँ: पीईटी सीटी और गामा नाइफ, शीर्ष बाल चिकित्सा केंद्र और एक नया रेन बसेरा (आश्रय) विकास के अधीन हैं।
- ड्रोन सुविधाः दूरदराज के क्षेत्रों में दवा वितरण के लिए लागू की गई।
- प्रशासनिक पहलः विभिन्न समितियों और पहलों के माध्यम से सुव्यवस्थित प्रशासन
- संकाय भर्तीः 2023 में 52 नए संकाय सदस्यों की भर्ती की गई।
- पदोन्नतिः विभिन्न कर्मचारी श्रेणियों में महत्वपूर्ण संख्या में पदोन्नति।
- मिशन रोज़गारः 1100 से ज़्यादा पद भरे गए।
- कॉलेजियम सिस्टमः फ़ैसले लेने में फैकल्टी की भागीदारी बढ़ाने के लिए सफलतापूर्वक लागू किया गया।
- डॉक्टर डेस्क मॉड्यूलः मरीज़ों की देखभाल और वर्कफ़्लो दक्षता में सुधार के लिए लागू किया गया।
- रोगी कल्याण समितिः 77 मरीज़ों को रूपये 71 लाख से ज़्यादा की मदद की गई।
- आउटरीच गतिविधियां: वंचित समुदायों को विस्तारित सेवाएँ
- मोबाइल टेस्टिंग वैनः नवंबर 2023 में शुरू की गई।
- चिकलोद क्लिनिकः ज़रूरी सेवाएँ प्रदान करना।
- निक्षय मित्रः टीबी के मरीज़ों की मदद करना।
- टीकाकरणः बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लक्षित करके महत्वपूर्ण टीकाकरण अभियान।
- आउटरीच गतिविधियाँ: गाँवों और व्यक्तियों को लक्षित करके।

मान्यता और पुरस्कार- एम्स भोपाल को अनेक मान्यताएँ प्राप्त हुई हैं-

- सभी सेवाओं के लिए एनएबीएच मान्यता।
- क्षेत्रीय वायरोलॉजी लैब के लिए एनएबीएल मान्यता।
- कायाकल्प मूल्यांकन में दूसरा स्थान।
- उत्कृष्टता केंद्र पदनाम।
- एफआईसीसीआई पुरस्कार 2023।
- स्वास्थ्य ऐप के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार।
- लगातार बढ़ती ओपीडी फुटफ़ॉल और उच्च बेड अधिभोग दर जनता के विश्वास को दर्शाती है।

सीएसआर पहल

3-डी बायोप्रिंटर के लिए फ़ंडिंग सहित महत्वपूर्ण सीएसआर दान प्राप्त हुए।

मंदिरम्

02

धर्मराजेश्वर मंदिर, मंदसौर

मंदसौर जिला मुख्यालय से 106 किमी दूर गरोठ तहसील का धर्मराजेश्वर मंदिर अपने आप में अनूठा है। धामनार मूल नाम वाले इस मंदिर को विशाल चट्टान काटकर बनाया है। इसमें शिखर पहले बना और नीचे का हिस्सा बाद में। गुफा मंदिर के नाम से भी पहचाने जाने वाला यह मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। मंदिर शिव और विष्णु दोनों को समर्पित है। इसके चारों ओर 1415 मीटर में सात छोटे मंदिर हैं। हर मंदिर एक अलग देवता को समर्पित है। मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ बड़ा शिवलिंग भी है। यहां 170 गुफाएं हैं, जो जैन सभ्यता से संबंधित हैं। गुफाओं में जैन तीर्थंकर ऋषभ देव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ और महावीर के रूप में वर्णित पांच मूर्तियां पाई गई हैं। हालांकि पांच होने से स्थानीय लोग इन्हें पांडवों की मूर्ति मानते हैं।

दिग्विजय सिंह के गढ़ में आरएसएस का 'राघौदय'

संघ का तीन दिवसीय शक्ति संगम आज से ; जुटेंगे तीन हजार स्वयंसेवक

गीत का हुआ विमोचन- बुधवार को राघौदय शक्ति संगम के संदर्भ में बनाएं गए गीत का विमोचन आरएसएस के विभाग संघ चालक अशोक सिंह कुशवाह के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

गुना (नप्र)। गुना जिले के राघौगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तीन हजार स्वयंसेवक जुटेंगे। यहां 3 से 5 जनवरी तक आरएसएस का तीन दिवसीय शक्ति संगम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम दौर में हैं।

जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश से पहले 'राघौदय शक्ति संगम' कार्यक्रम पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड राघौगढ़ में होगा। इसमें राघौगढ़ के खंड(तहसील) कुंभराज, चाचौड़ा, मधुसुदनगढ़ और राघौगढ़ के लगभग 3 हजार से अधिक स्वयंसेवक भाग लेंगे।

गुना विभाग के अंतर्गत राघौगढ़ जिले का यह पहला और बड़ा शक्ति संगम का कार्यक्रम है। शक्ति संगम का शुभारंभ शुक्रवार को महापुरुषों के जीवन चरित्र पर आधारित प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ होगा। इसके दूसरे दिन शनिवार नगर में स्वयंसेवकों का पथ संचलन निकाला जाएगा।

इस तीन दिवसीय शक्ति संगम का समापन रविवार 5 जनवरी को शिविर स्थल पर शारीरिक प्रदर्शन के साथ शक्ति संगम कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। तीनों ही दिन बौद्धिक भी होंगे। संघ के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी इसमें बौद्धिक देंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में मध्यप्रदेश के शासकीय कैलेंडर वर्ष -2025 का विमोचन किया।

परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 68वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ कर संबोधित किया।

भोपाल के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल के 1989 के ओल्ड स्टूडेंट्स का इंदौर में पुनर्मिलन कार्यक्रम

पहला दिन इंदौर में बिताया, दूसरे दिन महेश्वर में किले की भव्यता को निहारा

इंदौर। कार्मेल कॉन्वेंट भेल भोपाल के 1989 बैच के स्टूडेंट्स का पुनर्मिलन कार्यक्रम पिछले दिनों इंदौर और महेश्वर में मनाया गया। इस कार्यक्रम में उस बैच के 43 ओल्ड स्टूडेंट्स ने भाग लिया। कई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से भी आए थे। इनमें कई डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स थे।

पहले दिन 27 दिसंबर का मिलन कार्यक्रम इंदौर के सयाजी होटल में और दूसरे दिन का महेश्वर में हुआ। इस कार्यक्रम को इंदौर के उन ओल्ड स्टूडेंट्स ने आयोजित किया जो उस बैच का हिस्सा रहे हैं। सभी का मकसद स्कूल के दौर की पुरानी यादों को ताजा करना और उन पुराने रिश्तों को फिर से बनाना रहा। इस पुनर्मिलन कार्यक्रम की योजना और इंतजाम इंदौर स्थित उस बैच की कुछ साथियों ने किया। इनमें से कुछ लोग तो स्कूल से 12वीं पास करने के बाद 35 साल बाद मिले और दो दिन की ढेर सारी मीठी प्यारी यादें अपने साथ संजोकर ले गए। पहले दिन की शाम को जब सयाजी होटल में पार्टी में सब मिले तो सब का ख़ास तरह से स्वागत किया गया। प्रत्येक को एक टाइटल दिया गया, वो भी ख़ास तरह से जो या तो शायरी या गाने की तर्ज पर था। शाम की पार्टी में उद्घोषिका द्वारा बाँधा गया ख़ास समा एक स्वादिष्ट डिनर से सपन्न हुआ। जब स्कूल के ये पुराने पहली बार 27 दिसम्बर को मिले तो मन में बेहद उत्सुकता और तड़फ थी। जब सामने आए तो भावावेश में अपने आपको रोक नहीं सके और भाव विहल हो गए। लेकिन, दो दिन बाद जब बिछड़ने का समय आया तो सबका मन भारी था। आंखों से आंसू झर रहे थे और दिल में रिश्तों की करीबी और साथ बिताए पलों के मीठे पलों की ढेर सारी यादें थी। दो दिन बाद जब सभी साथी लौटे तो अपने साथ दिल को छूने वाली यादें लेकर गए।

इस पुनर्मिलन समारोह की मुख्य यादों में साथ खेले गए कुछ खेल रहे, जिन्हें जीतने वालों को इनाम भी दिए गए। विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप आकर्षक स्टोल दिए गए। कुछ ऐसे खेल भी इस कार्यक्रम के दौरान खेले गए, जिसे खेलते हुए इन ओल्ड स्टूडेंट्स ने बहुत मजे किए। सभी दिल खोलकर खेले और खूब हंसे। पासिंग द पार्सल खेल खेला गया पर एक खास ट्विस्ट के साथ। इंदौर से महेश्वर जाते समय बस में रास्ते भर खेली गई अंताक्षरी ने इस मिलन कार्यक्रम में एक अलग ही रंग भर दिया। पहली बार महेश्वर आए साथियों को महेश्वर के किले की सुंदरता और भव्यता ने मंत्रमुग्ध कर दिया। घाट पर नर्मदा मैया की आरती व बोटिंग से सहस्त्रधारा तक का नौका विहार साथियों को हमेशा याद रहेगा और उन्हें फिर मिलने और यहाँ आने के लिए प्रेरित भी करेगा।

निविदा में अनियमितता करने पर सहायक आयुक्त को कारण बताओ, एक निलंबित

समिति के गठन से पहले 23 दिसम्बर को निविदा विज्ञप्ति जारी की गई

(श्याम त्रिवेदी)

झाबुआ। कलेक्टर नेहा मीणा ने जनजातीय कार्य विभाग के भवन निर्माण एवं संधारण मरम्मत कार्यों की निविदा के संबंध में गंभीर अनियमितता बरतने पर एक कर्मचारी राजेश भावसार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जबकि, विभाग की सहायक आयुक्त निशा मेहरा को इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इन सभी निर्माण कार्य की लागत लगभग 17 करोड़ है।

जनजातीय कार्य विभाग में संचालित विभागीय शैक्षणिक/आवासीय संस्थाओ के स्वीकृत भवन निर्माण एवं संधारण मरम्मत कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। इस प्रक्रिया में समिति के गठन 27 दिसम्बर से पूर्व 23 दिसम्बर को ही निविदा विज्ञप्ति जारी कर दी गई, जिसे गंभीर अनियमितता माना गया। इस वजह से मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत जनजातीय कार्य विभाग के सहायक ग्रेड-2 राजेश भावसार को निलंबित कर दिया गया। साथ ही सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग निशा मेहरा को इस प्रकरण में कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए।

इस पर कार्रवाई हुई

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जिले में झाबुआ, थांदला, रामा, पेटलावद और रानापुर विकास खंड में 10 निर्माण कार्य किए जाने हैं। इनमें आदिवासी कन्या आश्रम का भवन निर्माण कार्य विद्युतिकरण, आदिवासी बालक आश्रम का भवन निर्माण कार्य मय विद्युतिकरण कार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में पेयजल कार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में सीमेंट कांक्रीट एप्रोच रोड निर्माण कार्य शामिल है।

लेकिन, जनजातीय कार्य विभाग की निविदा में एस्टीमेट की जानकारी ऑनलाइन अपलोड नहीं की गई। एस्टीमेट अपलोड नहीं होने से जिले के बाहर के कई ठेकेदारों को जानकारी के लिए झाबुआ आना पड़ेगा। जबकि अन्य जिलों में जनजातीय कार्य विभाग में होने वाले निर्माण कार्यों की ऑनलाइन बिड में एस्टीमेट अपलोड किया जाता है। निविदा में लिखा गया कि ठेकेदार को स्वीकृत कार्यों को गुणवत्तापूर्ण रूप से उपयुक्त सामग्री का उपयोग करते हुए विभागीय उपयंत्री के मार्गदर्शन में पूरा करना अनिवार्य होगा। लेकिन, विभाग में उपयंत्री का मूल पद ही रिक्त है और तकनीकी अधिकारी भी नहीं है।

सत्ता का सर्कस

दिनेश गुप्ता

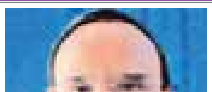

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

भ्रष्टाचार की कलई खोलती सीएजी की रिपोर्ट

महालेखाकार (सीएजी) की लेखा परीक्षा रिपोर्ट हर सरकार का आईन होती है। इस रिपोर्ट के जरिए सरकार को अपनी योजनाओं की जमीनी सच्चाई और अफसरों की नीयत का पता चल जाता है। विधानसभा के हाल ही समाप्त हुए शीतकालीन सत्र में भी सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर आई हैं। इन रिपोर्ट में विभिन्न विभागों के वित्तीय गड़बड़ी और हेराफेरी के कई चौंकाने वाले मामले उजागर हुए हैं। खासतौर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की टेक होम राशन योजना की रिपोर्ट यह बताती है कि अफसरों ने योजना की राशि जेब डालने के लिए कैसे दो पहिया वाहन के नंबरों का उपयोग ट्रक बताने में किया है। दो साल पहले जब विभाग को यह ऑडिट पैरा जवाब के लिए मिला था तब भी खूब हल्ला मचा था। तत्कालीन सरकार ने लिपिकीय त्रुटि बता कर इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की थी। विधानसभा में पेश हुई रिपोर्ट में महालेखाकार ने इस बारे में लिखा कि सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं है। ऐसे एक नहीं अनेक मामले रिपोर्ट में है। सरकारी अस्पतालों की जमीनी हकीकत बताने वाली रिपोर्ट भी इनमें एक है। रिपोर्ट से पता चलता है कि अफसर सीएजी रिपोर्ट के तथ्यों को लगातार झूठलाने की कोशिश करते रहे हैं। तब भी जब महालेखाकार के अधिकारी योजनाओं का लेखा-जोखा देख रहे होते हैं। गड़बड़ी पकड़ में आने पर अफसर हर स्तर पर सीएजी की टीम को भ्रमित करने की कोशिश भी करते हैं। सीएजी के अफसर कार्यालय का ऑडिट करते वक्त सरकार के नीति निर्देश, नियम, कानून और प्रक्रिया का भी पूरा ध्यान रखते हैं। ऑडिट में वित्तीय अनियमितता और गंभीर त्रुटि पकड़ में आने पर ही इसका ऑडिट पैरा बनाया जाता है। विधानसभा में पेश होने वाली अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इस पैरा को शामिल करने से पूर्व संबंधित कार्यालय अथवा विभाग को अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया जाता है। विभाग का उत्तर संतोषजनक न होने पर भी ऑडिट रिपोर्ट में इसे शामिल किया जाता है। रिपोर्ट को विधानसभा में पेश होने में डेढ़ से दो वर्ष का समय लग जाता है। विधानसभा में पेश हुई इस रिपोर्ट का परीक्षण लोक लेखा समिति द्वारा किया जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल का नेता है। लोक लेखा समिति ऑडिट रिपोर्ट पर विभाग के आला अधिकारियों से जवाब तलब करती है। समिति यदि अधिकारियों और सरकार के जवाब से संतुष्ट होती है तो प्रकरण समाप्त कर देती है। सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है।

मुरैना एवं श्योपुर कलेक्टर पर होगी कार्यवाही

मध्यप्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति द्वारा हाल ही में जिस मामले में दो जिलों के कलेक्टरों के खिलाफ कार्यवाही के लिए सरकार को लिखा है वह निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए की गई भर्ती से जुड़ा हुआ है। मामला 2018 का है। सीएजी ने 2018 में मुरैना एवं श्योपुर कलेक्टर कार्यालय का ऑडिट किया था। ऑडिट के दौरान यह पकड़ में आया कि इन जिलों के कलेक्टरों ने रिक्त पदों के विरूद्ध अनियमित रूप से सहायक ग्रेड तीन एवं भृत्य के पद नियुक्तियां की हैं। ये नियुक्तियां, नियुक्ति आदेशों से संबंधित भर्ती नियमों का उल्लेख किए बिना तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हकारी) परीक्षा नियम 2013 तथा फरवरी 2011 तथा मई 2011 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में निर्धारित उपयुक्त नियमित भर्ती प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई थीं। जनवरी 2016 से मार्च 2018 के मध्य अलग-अलग अवधि में वेतन एवं भत्तों के रूप में इन कर्मचारियों को 76 लाख 12 हजार रुपए का अनियमित भुगतान किया गया। इस ऑडिट पैरा के जवाब में राजस्व विभाग ने जुलाई 2019 में महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया कि कलेक्टर द्वारा की गई नियुक्ति अवैध हैं। सरकार ने प्रमुख राजस्व आयुक्त को नियुक्ति निरस्त करने के लिए कहा। मुरैना और श्योपुर जिले में अनियमित नियुक्तियों का मामला सामने आने के बाद महालेखाकार ने सरकार से कहा कि वह सभी जिलों की समीक्षा कर यह पता लगाए कि इस तरह की नियुक्ति कहीं अन्य तो नहीं हुई हैं। सरकार ने इस अनुशंसा पर क्या कार्यवाही की यह सामने नहीं आया है। लेकिन, लोक लेखा समिति ने इन अनियमित नियुक्तियों पर भुगतान किए गए वेतन की राशि तत्कालीन कलेक्टरों से वसूल करने के लिए सरकार से कहा है। जिस वक्त का यह मामला है उस वक्त मुरैना में विनोद शर्मा और श्योपुर में पन्नालाल सोलंकी कलेक्टर थे। इसके बाद मुरैना में प्रियंका दास और श्योपुर में बसंत कुर्रे कलेक्टर बन गए थे।

बच्चों का निवाला निगलने वालों पर सरकार की चुप्पी

महिला एवं बाल विकास विभाग की टेक होम राशन योजना में जिस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया है,वह इस बात की ओर इशारा करता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि अफसरों को सरकार का भी डर नहीं है। डर होता तो वे शायद दो पहिया वाहनों को ट्रक का नंबर बताकर घोटाला करने की हिम्मत ही न करते। सरकार भ्रष्टाचारियों को अपनी कथनी के अनुसार भी उल्टा टांगती तो आगे कोई आगे गड़बड़ी करने का साहस ही नहीं करता। रिपोर्ट के मुताबिक, महिला एवं बाल विकास विभाग ने साल 2018-21 के दौरान सभी कैटेगरी के 1.35 करोड़ हितग्राहियों के 4.04 मीट्रिक टन टेक होम राशन की खरीदी पर 2393.21 करोड़ रुपए खर्च किए। कैग ने आठ जिलों में 572.35 करोड़ के राशन वितरण की जांच की। इसमें पाया गया कि 11 से 14 साल की 5.51 लाख शाला त्यागी किशोरियों को 122.99 करोड़ मूल्य का 20291 मीट्रिक टन

राशन बांटा गया। लेकिन, फरवरी 2021 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोई जमीनी सर्वे नहीं किया। प्रमाणित डेटा न होने के बाद भी हितग्राहियों को टेक होम राशन के वितरण के आदेश दे दिए। कैग ने ये भी पाया कि बाड़ी, धार, मंडला, रीवा, सागर और शिवपुरी के प्लांट में स्टॉक न होने के बाद भी 277 चालानों के जरिए 178 प्रोजेक्ट्स को 773.21 मीट्रिक टन टेक होम राशन की आपूर्ति दिखा दी गई। कैग की टीम ने प्लांट और डीपीओ के दफ्तरों से मिले 40 चालानों का सत्यापन किया। इनमें से पांच फर्म- एमपी एग्रो न्यूट्री फूड्स लिमिटेड, एमपी एग्रोटॉनिक्स लिमिटेड, एमपीएसएआईडीसीएल, कोटा दाल मिल, राजस्थान और एमपी एग्रो फूड इंडस्ट्री लिमिटेड ने ट्रकों के जरिए 2.96 करोड़ के 479.46 मीट्रिक टन राशन की आपूर्ति बताई थी। वाहन पोर्टल पर ट्रकों के नंबर की जांच करने पर पता चला कि ये ट्रक नंबर मोटरसाइकिल, कार, ऑटो, ट्रैक्टर और टैंकर के रूप में रजिस्टर्ड थे। इसमें कैग ने प्लांट, ट्रांसपोर्टर और परियोजना अधिकारियों के बीच मिलीभगत पाई। साथ ही 2.5 करोड़ रुपए कीमत के 404 मीट्रिक टन राशन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। कैग ने आठ जिलों के डीपीओ के दस्तावेजों की जांच के दौरान पाया कि स्टॉक रजिस्टर के मुताबिक 96541.56 मीट्रिक टन राशन आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजा गया। परिवहन देयकों के सत्यापन से पता चला कि 86397.21 मीट्रिक टन राशन ही आंगनबाड़ी तक पहुंचाया गया यानी 10144.35 मीट्रिक टन राशन गायब पाया गया। इससे सरकार को 62.53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कैग के पूछने पर सरकार ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात की थी। कुल घोटाला चार सौ करोड़ रूपए से अधिक का है।

धोखाधड़ी से इनाम की कहानी

परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर से मिली करोड़ों रुपए की चल-अचल संपत्ति का मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में हैं। सौरभ शर्मा जैसे कई करोड़पति मध्यप्रदेश के विभिन्न विभागों में सक्रिय हैं। इनके रहन-सहन के स्तर से इनकी कहानी पता चल जाती है। कैग की रिपोर्ट में जरूर ऐसे अफसरों का सच सामने आने में समय लगता है। मध्य प्रदेश के अफसर हर वह काम कर सकते हैं,जिसे किसी अन्य राज्य के अफसर नहीं कर सकते। इस तरह की भी एक कहानी कैग की रिपोर्ट में है। यह रिपोर्ट बताती है कि अफसरों ने फर्जीवाड़ा कर किस तरह केंद्र सरकार से ईनाम लिया। राज्य सरकार ने भी अफसरों की खूब पीठ ठोंकी। मामला दिलचस्प है और बिजली से जुड़ा है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने झूठी रिपोर्ट पेश करके 50-50 लाख के इनाम के साथ ही केंद्र सरकार से 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान लिया है। जबकि सच्चाई यह है कि अभी लाखों घरों तक बिजली नहीं पहुंची। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना नाम से योजना चलाई थी इसके तहत हर गांव और हर घर में बिजली कनेक्शन पहुंचना था। इसके लिए केंद्र सरकार से बड़े पैमाने पर पैसा मिला था। राज्य की मध्य,पूर्व और पश्चिम तीनों बिजली कंपनियों ने दावा किया कि उन्होंने मध्यप्रदेश में सौ प्रतिशत बिजली कनेक्शन दे दिए हैं और हर घर तक बिजली पहुंचा दी है। नियम के अनुसार शत प्रतिशत काम करने वाले अधिकारियों को 50 लाख रुपये तक का इनाम मिलना था। अधिकारियों ने इस इनाम के साथ ही केंद्र सरकार से अतिरिक्त ढाईसो करोड़ रुपये का अनुदान भी प्राप्त कर लिया। सीएजी ने जब इस मामले की जानकारी ली तो सामने आया कि अधिकारियों ने सही ढंग से सर्वे ही नहीं किए हैं। अभी भी लाखों घरों तक बिजली नहीं पहुंची है। जिन घरों तक बिजली पहुंची ही नहीं है, उन्हें भी रिपोर्ट में कनेक्शनधारी बता दिया गया। सौभाग्य योजना के तहत दूर-दराज के ऐसे गांव, जहां बिजली की पहुंच नहीं है, वहां केंद्र सरकार ने हर परिवार को सोलर एनर्जी से 200 वॉट बिजली देने का फैसला किया था। इसके लिए हर घर में एक यूनिट लगाई जानी थी। प्रति यूनिट 31,348 रुपए हजार खर्च आना था। मप्र सरकार को इस योजना के लिए 1871 करोड़ रुपए मिले थे। राज्य सरकार ने कहा था कि वह योजना पर 10 प्रतिशत राशि व्यय करेगी। कैग की रिपोर्ट कहती है कि पूर्व क्षेत्र कंपनी ने इसके लिए लोन लिया और उसे मार्च 2022 तक ब्याज के तौर पर 24 करोड़ रुपए देने पड़े। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्यप्रदेश में बिजली कंपनियों ने पहले 50 वाट के पैनल 17,622 रुपए और फिर 150 वाट के पैनल 24,774 रुपए में लगाए। इस तरह हर यूनिट पर 11 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया। नया कनेक्शन देने के लिए केबल का खर्च 3 हजार रुपए फिक्स था लेकिन पूर्व क्षेत्र कंपनी ने दो तरह के केबल का इस्तेमाल किया। एक केबल के लिए 3514 रुपए और दूसरे के लिए 4461 रुपए के हिसाब से भुगतान कर दिया। ऐसे में प्रति कनेक्शन 946 रुपए का भुगतान किया गया। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे कंपनी को 11 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन का ठेका ई-टेंडर के माध्यम से दिया जाना था लेकिन पूर्व व पश्चिम विद्युत वितरण कंपनियों ने 1 लाख 38 हजार घरेलू कनेक्शन के लिए टुकड़ों में 4 हजार से ज्यादा वर्क ऑर्डर निकाले। इनके जरिए 50 करोड़ 62 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। इसी तरह कनेक्शन के लिए 4 एमएम का तार इस्तेमाल करना था लेकिन कैग ने जांच में पाया कि तीनों कंपनियों ने 3 लाख 36 हजार से ज्यादा घरों में बिजली कनेक्शन के लिए 2.5 एमएम के तार का इस्तेमाल किया। बिजली कंपनियों ने पहले बताया कि 9 लाख घर ऐसे हैं, जहां बिजली नहीं है। जब डीपीआर बनी तो ऐसे घरों की संख्या 9 लाख 77 हजार 056 हो गई। जब इसे संशोधित किया गया तो यह संख्या घटकर 5 लाख 4 हजार 841 रह गई जबकि वास्तविक घरों की संख्या 5 लाख 9 हजार 53 है। केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर 2018 को एक पुरस्कार शुरू किया था। जिसमें कहा गया था कि सौभाग्य योजना का कंपनी स्तर पर 30 नवंबर 2018 तक सो फीसदी घरेलू कनेक्शन देने का टारगेट था। मप्र की दो कंपनी- पश्चिम व मध्य विद्युत वितरण कंपनी ने इस टारगेट को पूरा करने का प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को भेज दिया था। इसके आधार पर केंद्र ने दोनों कंपनियों को सौ-सौ करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक जबकि यह टारगेट 2019 में पूरा हुआ था। पुरस्कार की अवधि निकल जाने के बाद मध्य क्षेत्र कंपनी ने 4 हजार 725 घरों में कनेक्शन करने के 24 वर्क ऑर्डर दिसंबर 2018 में जारी किए गए थे। यह काम अक्टूबर 2019 में पूरा किया गया था। इसी तरह पश्चिम क्षेत्र कंपनी ने यह टारगेट जून 2019 में पूरा किया था।